A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 09 अक्टूबर, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 41, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बिहार चुनाव- भाजपा व राजद के सामने चुनौतियाँ, जदयू व कांग्रेस मजबूत?

अरविंद मोहन

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या भाजपा और राजद के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं, और जदयू और कांग्रेस अपनी स्थिति मज़बूत की हुई हैं? ऐसे में किस गठबंधन का पलड़ा भारी होगा?

बीस साल से बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार जब हड़बड़ी में पटना मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे उसके कुछ घंटे बाद ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते पटना और प्रदेश के अन्य शहरों में लगे उन होर्डिंगों और प्रचार सामग्री को उतारने में मजदूर जुट गए, जिनसे राज्य सरकार आगामी चुनाव में कुछ लाभ पाने की उम्मीद कर रही है। मात्र तीन स्टेशनों के बीच मेट्रो चलाने की परियोजना भी इसी चलते हड़बड़ी में शुरू हुई। लेकिन नीतीश कुमार और उनके साथ सत्ता में भागीदारी कर रही बीजेपी को भरोसा है कि पचहत्तर लाख महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रुपए ट्रांसफर करने से लेकर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर वाली जिन लगभग एक दर्जन योजनाओं की घोषणा पिछले कुछ महीनों के अंदर हुई है, वह बीस साल के एंटी-इंकम्बेन्सी को काटकर एनडीए को जीत दिला देगी। विपक्ष भी इस बारे में मुंह खोलने और आलोचना करने से बच रहा है, क्योंकि इससे उसकी छवि खराब होगी। सो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर उनकी योजनाएं चुराने का आरोप लगा रहे हैं।

कहना न होगा कि अब वे वोट चोरी के सवाल को उस तरह उठाने का उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, जैसा डेढ़-दो महीने पहले कर रहे थे। इस मुद्दे को बहुत जोर-शोर से उठाने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी तो अचानक बिहार के राजनैतिक परिदृश्य से कुछ समय गायब हो गए, लेकिन वोट चोरी का मसला सुप्रीम कोर्ट के कई बार दिए गए दखल से काफी कुछ लाइन पर आया और चुनाव आयोग तथा शासक गठबंधन ने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण पर पहले जैसी गलतियां न करके मामले को कुछ ठंडा पड़ने दिया है।

इस बीच प्रशांत किशोर ने प्रदेश भाजपा के चार प्रमुख नेताओं और नीतीश कुमार के एक दुलारे मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाकर बिहार में काफी खलबली मचाई है और वोट चोरी के सवाल को भी पीछे किया है। पर तेजस्वी की मुश्किल यह है कि वे भ्रष्टाचार के सवाल को भी ज़्यादा जोर से नहीं उठा सकते क्योंकि लालू यादव का सजायाफ़्ता होना और खुद तेजस्वी समेत सारे परिवार के अभी भी आरोपों में घिरे होने से यह सवाल उनके चुनावी भविष्य के लिए मुश्किल बन सकता है। बीजेपी ने जिस सम्राट चौधरी पर दांव लगाया था वे तो प्रशांत के आरोपों से लहू-लुहान हुए ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दो पूर्व अध्यक्ष-संजय जायसवाल तथा मंगल पांडेय भी बुरी तरह घिर गए हैं।

लेकिन जिस भाजपा के लिए इस बार बिहार जीतने का मौका था, वह सचमुच मुंह छुपा रही है या नीतीश को आगे करके लोक-लुभावन कार्यक्रमों और पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। पैंतीस साल से एक ही तरह की राजनीति और शासन झेल रहे बिहार को नई राजनीति चाहिए लेकिन न तो भाजपा उसके लिए तैयार है और न प्रशांत किशोर खुद को विकल्प के रूप में पेश कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, होशियार हैं लेकिन उनका अगड़ा होना और पैसों के संदिग्ध स्रोत उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

भाजपा तो जैसे-जैसे अपने पैरों पर खड़ा होने की जगह नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे छुप रही है, वैसे-वैसे उसका स्वतंत्र ढंग से बिहार की राजनीति में बढ़ना थम गया है। खुद थक हार गए नीतीश कुमार अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं तो भाजपा को क्या सहारा देंगे।

नीतीश की ईमानदार वाली छवि है और उसने बीस साल का राज दिलवा दिया है। पर जैसे जैसे भाजपा के नेताओं का ग्राफ गिरा है नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति बढ़ती गई है। वह चुनाव जितवा देगी यह कहना जल्दबाजी होगी। पर खुद को असहाय पाती भाजपा इस बार चिराग पासवान, पप्पू यादव और ओवैसी जैसों के सहारे नीतीश और विपक्ष को पंचर करने का दोहरा खेल इस बार नहीं खेल पा रही है।

बीजेपी के बाद सबसे मजबूत दल राजद का किस्सा हल्का बयान हुआ है पर यह भी कहना जरूरी है कि इस बार वह मुसलमान वोट के पूरी तरह इंडिया गठबंधन की तरफ आने से बम-बम हैं। वक्फ कानून पर भाजपा का साथ देने से नीतीश कुमार पर मुसलमानों का भरोसा पूरी तरह टूट गया है। लेकिन उसी अनुपात में कांग्रेस का ग्राफ चढ़ा भी है। इसलिए तेजस्वी या राजद को इस सच्चाई को ध्यान में रखना होगा। और कांग्रेस ने रविदासियों, मुसहरों और अति पिछड़ा समाज में घुसपैठ करने की गंभीर कोशिशें की हैं जैसा यादव दबदबे वाली राजद नहीं कर पाई है।

लगभग 36 फीसदी आबादी वाला अति पिछड़ा समाज भी हाल के वर्षों में अपने विरोधाभासों से जूझता रहा है और वह एक साथ वोट देगा यह मानना जल्दबाजी होगी। उसे नीतीश कुमार का भरोसा है पर वह यह भी देख रहा है कि वे अब राजनीति में ज्यादा समय चलने वाले नहीं हैं। और अगर यह वोट बैंक बिखरा तो कहां जाएगा, यह कहना अभी भी मुश्किल है। पर इतना कहा जा सकता है कि अगर भाजपा अपने दम पर होती तो इस समाज के उसके पास जाने का सबसे ज्यादा अवसर था।

भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे, अमित शाह की चौकस व्यवस्था, केंद्र के धन के साथ अपने अपार संसाधनों के बल पर है लेकिन स्थानीय नेतृत्व के मामले में कमजोर पड़ने से उसकी तकलीफ बढ़ रही है। और सिर्फ पिछड़ा नेता सामने करने के चलते उसे अगड़ों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है जो इस बार प्रशांत किशोर का नाम लेने लगा है। यह सिर्फ भाजपा को डराने और ज्यादा टिकट के लिए दबाव बनाने के लिए है यह जल्दी ही साफ हो जाएगा। ज्यादा नए वोटर कांग्रेस से जुड़ें तो भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सवाल को जिस तरह उठाया है, वैसा कोई और नहीं कर पाया है। यह ज़रूर है कि मजबूत संगठन और सामाजिक आधार न होने से कांग्रेस बूथ स्तर पर भाजपा या एनडीए का मुकाबला करती नहीं लगती लेकिन चुनाव में लोगों का मन ही सर्वोपरि महत्व की चीज है। इसलिए कांग्रेस और जदयू बढ़ें तथा राजद और भाजपा की सीटें घटें तो हैरान न होइएगा। कम से कम इस लेखक को प्रशांत किशोर से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी कलेक्टर्स की

- घटना हो या दुर्घटना, तत्काल मौके पर पहुंचे
- जन सुरक्षा, सुशासन और सेवा भाव हो प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
- पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय कर ड्रग कारोबार को करें नेस्तनाबूत
- कलेक्टर्स एवं एसपी विकसित करें खुद का सूचना तंत्र
- मध्यप्रदेश को अगले 6 महीने में बनाए नक्सल मुक्त प्रदेश
- कानून एवं व्यवस्था पर हुआ कांन्फ्रेंस का आंठवा और अंतिम सत्र

भोपाल (नप्र)। कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस 2025-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कलेक्टर्स जिले के प्रशासनिक मुखिया होने के साथ-साथ जिला दण्डाधिकारी भी हैं, इसीलिए जिले में कानून व्यवस्था की बहाली सुनिश्चित करने की पहली जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।

उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में खुद का प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें, ताकि किसी भी घटना या दुर्घटना की सूचना तत्काल प्राप्त हो और समय पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी घटना या दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे। इससे घटना या दुर्घटना और अधिक बड़ा रूप नहीं लेंगी। जिला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से स्थिति नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कलेक्टर एवं एसपी दोनों में उच्च कोटि का तालमेल होना चाहिए। दोनों संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर जिले की कानून व्यवस्था की निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ऐसी संवेदनशील बस्तियां जहां सड़कें सकरी हैं, तथा फोर्स मूवमेंट में समस्या आती है, सभी कलेक्टर्स ऐसे स्पॉट्स/जगहों को चिन्हित कर वहां का जोनल प्लान स्थानीय नगरीय निकायों के सहयोग से अगले तीन माह में तैयार कर लें, ताकि आवागमन सुगम हो और आवश्यकता पड़ने पर फोर्स मूवमेंट में समस्या न आए। उन्होंने मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025 के आठवें एवं अंतिम सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सेंसिटिव पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भाव होना चाहिए। पुलिस अपनी

साख बनाएं और अपराधों को रोकने में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करें। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स-एसपी की संयुक्त कॉन्फ्रेंस का विषय कानून एवं व्यवस्था की सुनिश्चितता था। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की मौजूदगी में हुए इस अंतिम सत्र का संचालन अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री शिवशेखर शुक्ला ने किया। सत्र में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मध्यप्रदेश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त करने के दृष्टिगत 6 माहों में बालाघाट, मण्डला और डिण्डोरी जिलों के कलेक्टर्स और एसपी लक्ष्य केंद्रित कर यह काम पूरा करें। उन्होंने कहा कि नक्सली घटनाओं को समाप्त करने के लिए हर संभव कार्यवाही करें। नक्सली या तो सरेंडर करें अन्यथा उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियों में बेहद कमी आने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बालाघाट को अति नक्सलवाद प्रभावित जिले की श्रेणी से डाउनग्रेड कर सामान्य श्रेणी में कर दिया है। उन्होंने इस उपलब्धि पर कलेक्टर-एसपी बालाघाट दोनों को बधाई दी। बताया गया कि कलेक्टर बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित ग्रामों में विशेष प्रयास करके 200 से अधिक युवाओं को एलएनटी जैसी कंपनी में रोजगार दिलाया है। इससे वह दिशाभ्रमित होने से बच गए और समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस साल ही हमने आठ मुठभेड़ में दस नक्सली मार गिराए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए पुलिस एवं अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य करें, इस काम में और सख्ती लाएं। उन्होंने बताया कि अब तक 19 बांग्लादेशियों को चिन्हित कर वापस भेजा गया है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रखें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल एवं कॉलेज के आसपास आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए सूचना तंत्र विकसित करें, निगरानी तंत्र को और तेज करें और ऐसे चिन्हित स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं।

प्रदेश में ड्रग्स के अवैध कारोबार एवं नशे पर सख्ती करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ड्रग्स के अवैध कारोबार एवं नशे पर अंकुश लगाने के लिए पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वय करते हुए हर स्तर पर नशे को प्रतिबंधित किया जाए। इसी कड़ी में कोरेक्स कफ सिरप के अतिशय उपयोग को भी नियंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि ड्रग एवं अन्य नशे के पदार्थ के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में कलेक्टर-एसपी तालमेल करके बारीक निगाहे रखें। इनका लगातार निरीक्षण होता रहे। कोरेक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए उच्च स्तर पर विचार कर समाधान निकालें। शेड्यूल एच ड्रग्स ओवर द काउंटर ना बिकें और सभी दवाइयों का हिसाब भी फार्मासिस्ट अनिवार्य रूप से रखें।

मप्र में जहरीले सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत

छिंदवाड़ा में सिविल सर्जन को हटाया

ड्रग इंस्पेक्टर ने डिप्टी सीएम को गिनाई लैब की खामियां

भोपाल/छिंदवाड़ा (नप्र)। मध्यप्रदेश में जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। इस मामले में एक और एक्शन हुआ है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन

नरेश गोन्नाड़े को हटा दिया है। उनकी जगह डॉ. सुशील दुबे नए सिविल सर्जन बनाए गए हैं। नरेश गोन्नाड़े सीएमएचओ भी हैं, उनके पास सिविल सर्जन का प्रभार भी था। जिसके बाद उनसे सिविल सर्जन का चार्ज वापस ले लिया गया है। इससे पहले बुधवार को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने उन्हें लैब की खामियां गिनाई। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे और दिवंगत बच्चों के परिजनों से भेंट की। उन्होंने परिवारजनों से बातचीत कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें ढांढस बंधाया।

निर्माणाधीन सिम्स मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कफ सिरफ प्रकरण में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में एडीएम श्री धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में उक्त कफ सिरप की कुल 594 बोतलें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से अब तक 430 बोतलें जब्त की जा चुकी हैं। 12 बोतलों के नमूने जांच हेतु लिए गए, 1 बोतल फ्रीज की गई। बैठक के पश्चात उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्माणाधीन सिम्स मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। (शेष- पेज-8 पर)

सुप्रभात

खुद को इतना भी मत बचाया कर
बारिशें हों तो भीग जाया कर
काम ले कुछ हसीन होंठों से
बातों-बातों में मुस्कुराया कर
चाँद लाकर कोई नहीं देगा
अपने चेहरे से जगमगाया कर
धूप मायूस लौट जाती है
छत पे कपड़े सुखाने आया कर
घर से बाहर निकल हवाओं में
ज़ुल्फ़ से खुशबुएँ उड़ाया कर
कौन कहता है दिल मिलाने को
कम से कम हाथ तो मिलाया कर।

– शकील आजमी

ओबीसी आरक्षण केस, हाईकोर्ट को वापस भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट

राज्य की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय बेहतर जानता है, आज आ सकता है बड़ा फैसला

भोपाल (नप्र)। एमपी में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मप्र के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और स्पेशल काउंसिल एडवोकेट शशांक रतनू सरकार की ओर से मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के मामले में आज गुरुवार को बड़ा फैसला दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मैटर को मेंशन किया। मेहता ने कहा- इसमें बहुत सारे टेक्निकल पक्ष हैं। इसलिए कहीं न कहीं इसकी सुनवाई में समय लग सकता है।

इसके समाधान के लिए क्या तरीका निकाला जाए? क्यों न कुछ और तरह का सॉल्यूशन निकाला जाए।

कोर्ट ने कहा- और वक्त मांगेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी

इस पर कोर्ट ने कहा कि आप फिर वक्त मांगेंगे तो और समय जाएगा। दिक्कतें बढ़ेंगी। अगले हफ्ते दीवाली है, छुट्टियां हैं। कोर्ट ने कहा, हम ये चाहते हैं कि ये मैटर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन पहुंची हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ की तरह अंतरिम राहत दे सकता है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में अंतरिम लाभ दिया गया था। हो सकता है कि मप्र के मामले में भी अंतरिम राहत दे दें। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर जो उपयुक्त समाधान हो सकता है उस पर कल विवेचना करके सुनवाई करेंगे।

तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद को केसों से हटाया

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच ही बुधवार को मप्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण मामले में तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद पी विल्सन को केसों से हटा दिया है। इस बारे में सरकार ने आदेश जारी किया है। इसमें नए अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। इसमें आर. वेंकटरमानी, तुषार मेहता, केएम नटराज और प्रशांत सिंह की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

कांग्रेस बताए पाकिस्तान पर क्यों नहीं किया हमला

- चिदंबरम का जिक्र करके पीएम मोदी ने मुंबई में किया बड़ा अटैक

पीएम मोदी ने मुंबई दौरे में नवी मुंबई एयरपोर्ट का किया शुभारंभ

मुंबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे में बुधवार को बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ मुंबईवासियों को मेट्रो 3 की सौगात दी। पीएम मोदी ने इसके बाद मुंबई वन एप का भी शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा मुंबई भारत का अहम शहर है, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए मुंबई को चुना था, लेकिन 26/11 बाद मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने कमजोरी का मैसेज दिया। उसने आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का सबूत दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता (चिदंबरम) यह कह चुके हैं।

- **महाराष्ट्र के किसान यूरोप से जुड़ जाएंगे-** नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में विकसित भारत की झलक है। कमल के फूल जैसा आकार है। यानी संस्कृति का प्रतीक है। महाराष्ट्र के किसान यूरोप से जुड़ जाएंगे। जिससे उनकी उपज इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। जब सपने को सिद्ध करने का संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो नतीजे भी मिलते हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 30 °c | न्यूनतम 25°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 09 अक्टूबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सिंगर जुबिन गर्ग मौत केस में चचेरा भाई गिरफ्तार

हादसे के समय जुबिन के साथ मौजूद था, अभी असम पुलिस में डीएसपी

गुवाहाटी (एजेंसी)। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में बुधवार को असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को अरेस्ट किया गया है। संदीपन, सिंगर के चचेरे भाई हैं। हादसे के वक्त वह सिंगापुर में साथ थे। अधिकारी ने बताया कि संदीपन से जुबिन की मौत के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षडयंत्र

और लापरवाही से मौत का कारण बनने का केस दर्ज किया गया है। जुबिन की मौत के मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टीवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके दो बैंड सदस्यों - शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को अरेस्ट किया गया था। जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में 19 सितंबर को हुआ था। सिंगर 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टीवल के लिए सिंगापुर गए हुए थे, जहां उन्होंने वाटर एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। दावा किया गया कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में हुई थी।

जेल से छूटने के बाद आजम-अखिलेश की पहली मुलाकात

रामपुर में सपा प्रमुख बोले-आजम परिवार पर भाजपा केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है

रामपुर (एजेंसी)। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल से छूटने के बाद पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान आजम की पत्नी और बेटे भी मौजूद नहीं थे। बाहर निकलने पर अखिलेश ने कहा- आजम साहब बहुत पुराने नेता हैं। उनका गहरा साया हमेशा हमारे साथ रहा

है। आजम खान हमारी पार्टी की दरख्त (पेड़) हैं। आजम परिवार पर भाजपा केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यह बड़ी लड़ाई है और उसमें हम सब मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले, सपा प्रमुख को आजम ने खुद रिसीव किया। इसके बाद अखिलेश और आजम एक ही कार में बैठकर घर पहुंचे। अखिलेश बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे लखनऊ से निजी विमान से रामपुर के लिए रवाना हुए थे। वह पहले बरेली एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से हेलीकॉप्टर से दोपहर 12.45 बजे रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी लैंड हुए। इधर, आजम की नाराजगी के चलते अखिलेश ने रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया।

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने रानी मुखर्जी के साथ देखी फिल्म

● यशराज स्टूडियो का दौरा किया, 100 मेंबर का डेलिगेशन लेकर मुंबई पहुंचे

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने बुधवार को मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ फिल्म देखी। उन्होंने यशराज स्टूडियो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीईओ अक्षय विधानी से भी मुलाकात की। उन्होंने कौन सी फिल्म देखी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्टार्मर बुधवार को ही मुंबई पहुंचे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। उनके साथ व्यापार, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों के 100 से अधिक लोगों का एक डेलीगेशन भी आया है, जिसमें आईटी, ऑटो-मोबाइल सहित कई क्षेत्रों के कारोबारी भी शामिल हैं। स्टार्मर और पीएम मोदी के बीच कल मुंबई में एक कार्यक्रम में मुलाकात होगी और 'विजन 2030' के तहत साझेदारी के डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। इसी साल जुलाई में भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर दस्तखत हुआ था। यह समझौता का मकसद आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। एफटीए से भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे- कपड़े, चमड़ा और एग्री प्रोडक्ट को ब्रिटेन में बेचना आसान हो जाएगा। अब स्टार्मर का दौरा दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टारमर ने कहा है कि उनका देश भारत के लिए वीजा नियमों में कोई ढील नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ाने के बड़े मौके हैं, लेकिन भारतीय कामगारों या छात्रों के लिए नए वीजा रास्ते खोलने की कोई योजना नहीं है। लेबर सरकार इस समय ब्रिटेन में आने वाले प्रवासियों की संख्या घटाने की कोशिश कर रही है। स्टार्मर ने दोहराया कि भारत के साथ हुए व्यापार समझौते में वीजा का कोई रोल नहीं था।

स्टार्मर बोले-

● **ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक मिशन-** स्टार्मर ने मुंबई आने से पहले डेलिगेशन का अनोखे अंदाज में स्वागत किया। उन्होंने खुद कॉकपिट में जाकर घोषणा की, मैं आपका प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। यह कोई साधारण उड़ान नहीं है, बल्कि ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक मिशन है। जो भारत के साथ नए व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। स्टार्मर ने इंस्टाग्राम पर इस पल का वीडियो साझा करते हुए कहा, आप सभी का इस फ्लाइट में स्वागत है। हम नए मुक्त व्यापार समझौते के तहत सभी संभावनाओं को तलाशने के लिए उत्सुक हैं। स्टार्मर और मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में हिस्सा लेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इवेंट है, जो 7 से 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसका एजेंडा फाइनेंस को मजबूत बनाना है।

करीब एक हजार ट्रैक्टर लेकर आए किसान, 2 किमी लंबा जाम

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को निरस्त करने की मांग, जमकर की नारेबाजी

भोपाल/इंदौर (नप्र)। इंदौर में बुधवार को किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को निरस्त करने की मांग की। साथ ही सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने और मुआवजा दर बढ़ाने जैसी मांगें भी रखी। इसे लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन में इंदौर और उज्जैन जिले के किसान करीब एक हजार ट्रैक्टर लेकर इंदौर आए थे। 5 हजार से ज्यादा किसान हातोद और आसपास के गांवों से रैली के रूप में आए। किसानों ने सरकार और कांग्रेस दोनों के खिलाफ नारेबाजी की।

किसानों के प्रदर्शन के दौरान धार रोड पर करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी कतारें यहां नजर आई।

कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे किसान, बीच में रोका

किसान कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर ले जाने पर अड़े थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें धार रोड पर नूरानी नगर के पास ही रोक दिया। रैली के दौरान करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने किसानों से अपील की.. कि चुनाव के समय नेताओं को गांव में घुसने न दें। इसके बाद किसानों ने एडीएम रोशन रॉय को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं और प्रदर्शन समाप्त किया।

ग्रीन फील्ड कॉरिडोर से 28 गांव प्रभावित- इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना से इंदौर की सांवेर और हातोद तहसीलों के करीब 20 गांव व उज्जैन जिले के 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के लिए 188 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। कई किसानों की पूरी जमीन परियोजना की जद में आ रही है, जबकि कुछ की जमीन के बीच से सड़क गुजरेगी।

बिना सर्वे के योजना लागू करने का आरोप

किसान नेता बबलू जाधव ने कहा कि सरकार ने बिना पर्याप्त सर्वे और आकलन के यह योजना लागू कर दी है। इससे किसानों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि यह सड़क 2028 के सिंहस्थ को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, लेकिन उज्जैन जाने के पहले से ही कई मार्ग हैं जिन्हें चौड़ा कर यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। लगातार नीतियों और योजनाओं में किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है। जाधव ने कहा- सरकार योजनाएं बना देती है, लेकिन अन्नदाता की स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करती।

आंध्र की पटाखा फैक्ट्री में आग, छह लोगों की मौत

रायवरम (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले के रायवरम में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके बाद धमाके भी हुए। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। एसपी राहुल मीणा ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री में लापरवाही के कारण हादसे की आशंका है। पटाखा फैक्ट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में पटाखा बनाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका की खबरें हैं। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिरी दिखी। एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति का शव पूरी तरह जला हुआ पड़ा है। वहीं, वीडियो में फैक्ट्री से धुएं का गुबार दिख रहा है।

केमिस्ट्री का नोबेल जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को

● एटम के नए डिजाइन बनाए; प्रदूषण हटाने, रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने में इस्तेमाल

स्टॉकहोम (एजेंसी)। इस साल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा (जापान), रिचर्ड रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया) और उमर एम. याघी (अमेरिका) को मिला है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इन्होंने ऐसे एटम बनाए हैं जिनमें बड़े-बड़े खाली हिस्से होते हैं, जिनसे गैस और अन्य रासायनिक पदार्थ आसानी से गुजर सकते हैं। इन संरचनाओं को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कहते हैं। इसमें

ऐसे क्रिस्टल बनते हैं, जिनमें बड़े खाली हिस्से होते हैं। ये खास तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं ताकि वे किसी खास चीज को कैप्चर कर सकें या स्टोर कर सकें। इनका इस्तेमाल रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने, प्रदूषण हटाने, कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने, जहरीली गैसों को स्टोर करने या रासायनिक क्रियाएं तेज करने में किया जा सकता है। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (10.3 करोड़ रुपए), सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा।

भारत ने दोस्त इजराइल से की नई मिसाइल डील !

● सुखोई में रैम्पेज मिसाइल से टेंशन में होगा पाकिस्तान

अब कई गुना बढ़ जाएगी भारतीय वायुसेना की ताकत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वायु सेना ने फाइटर जेट सुखोई को और पॉवरफुल बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हिल जाएगा। एयरफोर्स ने अपने दोस्त इजरायल से 2000 किमी प्रति घंटे की स्पीड वाली खतरनाक रैम्पेज मिसाइल को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने ये फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि एसयू-30 एमकेआई के साथ 2000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस सुपरसोनिक मिसाइल के जुड़ने से ये एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम को भी चकमा दे सकती है। इजरायली

रैम्पेज मिसाइल के सुखोई के साथ आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस एकीकरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह वायु सेना के हथियारों में एक बड़ा सुधार है और दुश्मनों के लिए गंभीर खतरा है।

आज होगा आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमॉर्टम

● बेटी के अमेरिका से चंडीगढ़ आने का हो रहा है इंतजार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार का पोस्टमॉर्टम कल 9 अक्टूबर को होगा। उनका शव चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रखा गया है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया है कि आईजी की बड़ी बेटी अभी अमेरिका से चंडीगढ़ नहीं पहुंची है। पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने भी बेटी के आने के बाद ही पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार पर सहमति जताई है। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी. कुमार बुधवार को जापान दौरे से चंडीगढ़ लौट आईं। पहले वह सेक्टर-24 स्थित सरकारी आवास पर पहुंचीं। यहां चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी समेत कई बड़े अफसरों ने उनसे मुलाकात की।

धोखाधड़ी मामले में शिल्पा 'हाई' झटका

विदेश जाने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने दिखाया आईना

बोला- पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विचार करेंगे

मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है। दरअसल, 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर/नोटिस जारी किया गया था, जिससे उनके विदेश भागने पर रोक लगाई जा सके। हालांकि, एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर करते हुए विदेश यात्रा की इजाजत

मांगी थी। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि अगर वो विदेश जाना चाहती हैं तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने याचिका में 4 ट्रिप की इजाजत मांगी थी। पहली ट्रिप 2 अक्टूबर-5 अक्टूबर तक थाईलैंड की होनी थी। जो अब मुमकिन नहीं है। दूसरी इजाजत उन्होंने 21 से 24 अक्टूबर तक लॉस एंजिलिस की और तीसरी 25 अक्टूबर को कोलंबो की ट्रिप की भी परमीशन मांगी है।

ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन गौरव से भर देता है

● एयरफोर्स चीफ बोले-पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिन में धूल चटाई ● कहा-योजना और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल कर सकते हैं

गाजियाबाद (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना का 93वां वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर मनाया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने शत्रु पर सिर्फ चार दिनों में विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा- ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन हमें पेशेवर गौरव से भर देता है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि सावधानी के साथ योजना बनाकर, अनुशासन के साथ ट्रेनिंग और दृढ़ निश्चय के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। स्वदेशी हथियारों ने दुश्मन के इलाके में अंदर तक सटीक प्रहार किए। इससे पहले वायुसेना के विमानों ने शानदार करतब दिखाए।

● **वायु योद्धाओं में जवाबदेही की संस्कृति बढ़ी-** एयर चीफ मार्शल बोले- हमारे लिए नई प्रणालियों, हथियारों और उपकरणों के एकीकरण की बढ़ी हुई गति अहम सफलता रही है। मैं देख सकता हूं कि वायु योद्धाओं में जवाबदेही और सुरक्षा की संस्कृति बढ़ी है। यह साफ दिखाई भी दे रहा है। सभी स्तरों पर वायुवीर आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और असाधारण दूरदर्शिता और सहानुभूति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक प्रशिक्षण मिले और वह प्रेरित हो।

सीएम ने भारतीय वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दीं

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत के गौरव, आकाश के अभेद प्रहरी भारतीय वायुसेना के सभी जवानों और उनके परिजनों को भारतीय वायु सेना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नभः स्पृशं दीप्तम् मंत्र के साथ चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो या आपदा के समय लोगों को राहत पहुंचाना, देश के वायु वीरों ने हमेशा अपने शौर्य, साहस और त्याग के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेवा की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अर्पित की श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'भारत रत्न' से सम्मानित जयप्रकाश जी का सम्पूर्ण जीवन देशभक्ति का महान पाथेय है। उन्होंने आपातकाल के अंधकार से देश को निकालने के लिए जो 'सम्पूर्ण क्रांति' की वह सदियों तक मां भारती एवं लोकतंत्र की सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पासवान को दी श्रद्धांजलि

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकप्रिय राजनेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. पासवान आजीवन गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की आवाज बने रहे। भारतीय राजनीति में उन्हें सामाजिक न्याय के सशक्त आधार के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।

मुंशी प्रेमचंद का किया स्मरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी से मानवीय संवेदनाओं, आडंबरों और आमजन के संघर्षों को शब्दों में पिरोकर मानव-कल्याण के नए-नए मार्ग दिखाए हैं। उनकी कालजयी रचनाओं से साहित्य जगत अनंत काल तक आलोकित होता रहेगा।

शराब पीने पर बेटे ने टोका पिता ने लगा ली फांसी

● भोपाल में हुआ था विवाद, रोजाना नशे की हालत में घर आते थे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार इलाके में नशे में घर आए पिता को बेटे ने टोक दिया। उन्हें शराब न पीने के लिए समझाइश दी तो गुस्साए पिता ने अपशब्द कहना शुरू कर दिए। नाराज बेटा घर से चला गया, कुछ देर बाद लौटा तो पिता फांसी लगा चुके थे। घटना मंगलवार देर रात की है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कोलार थाने के एसआई जोगेन्द्र नेगी ने बताया कि 50 वर्षीय शिवघाड़गे कान्हाकुंज में रहते थे। वे फर्नीचर की दुकान पर काम करते थे, इसी के साथ कॉलोनी की चौकीदारी भी करते थे। उनकी चार बेटियां व एक बेटा है। चार में से तीन बेटियों की शादी हो गई है। दो दिन पहले पत्नी अपनी बेटी को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के घर खंडवा चली गई थी।

घर में बेटा और शिवराम ही थे। शिवराम को शराब पीने की लत थी। तकरीबन रोजाना ही नशे की हालत में घर आते थे। मंगलवार की रात वे नशे की हालत में ही घर पहुंचे। घर में मौजूद बेटे ने टोका तो उन्होंने बेटे को जमकर फटकार दिया। नाराज होकर बेटा उस समय घर से बाहर चला गया। रात करीब 11.30 बजे बजे वह वापस आया तो पिता शिवराम फंदे पर लटके मिले। बेटा फंदे से उतारकर अस्पताल ले गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ज्यादा नंबर वाले वोटर्स के घर जाएगी कांग्रेस

● नए जुड़े-कटे नामों तक भी पहुंचेगी, बीजेपी के पन्ना प्रमुख के मुकाबले कांग्रेस के बीएलए

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस अब वोटर लिस्ट सुधार को लेकर तेजी से काम कर रही है। भाजपा के पन्ना प्रमुखों के मुकाबले कांग्रेस अब हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात कर रही है। 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने प्रदेशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में कांग्रेस अब ज्यादा नंबर वाले वोटर्स के घर जाएगी, जो भी नए नाम जुड़ेंगे-कटेंगे उन तक भी पहुंचेगी। कांग्रेस अब केवल प्रचार तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि मतदाता सूची के हर पन्ने और हर नाम पर अपनी निगरानी रखने पर तेजी से काम करेगी।

नाम जुड़वाने, कटवाने की ट्रेनिंग देंगे - कांग्रेस सभी बीएलए को निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं जैसे फॉर्म-6 (नाम जोड़ना), फॉर्म-7 (नाम हटाना), फॉर्म-8 (सुधार) और फॉर्म-8ए (स्थानांतरण) की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

बीएलओ के सीधे संपर्क में होंगे कांग्रेस के बीएलए - कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट सीधे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के संपर्क में रहेंगे। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बीएलओ घर-घर जाकर एनेक्सचर-सी भरवाएंगे, जो मतदाता की पात्रता प्रमाणित करने का दस्तावेज होगा। कांग्रेस ने अपने बीएलए को यह जिम्मेदारी दी है कि वे इस सर्वे में शामिल होकर हर वोटर का विवरण सही तरीके से दर्ज करवाएं।

हर विधानसभा में बनेगा कांग्रेस कंट्रोल रूम - प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में 'मतदाता सूची नियंत्रण कक्ष' बनाएगी। जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ऑफलाइन मतदाता सूची दोनों से डेटा एकत्र करेगा। इस कंट्रोल रूम से वोटर लिस्ट में छूटे नामों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कंट्रोल रूम पार्टी के हर बीएलए से फीडबैक लेगा और स्थानीय स्तर पर शिकायतों का समाधान कराने पार्टी स्तर पर सूचित करेगा।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता शत-प्रतिशत हो : मुख्य सचिव जैन

● शालाओं में बच्चों के नामांकन की दर में करें सुधार ● शाला विकास समिति में बच्चों के पालक सहित शिक्षा में रूचि रखने वाले हों शामिल ● शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये अन्य विभागों के लोगों को भी जोड़ें

भोपाल (नप्र)। कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार सत्र में जोर देकर कहा कि विकसित भारत के रोडमेप में शिक्षा एक मूलभूत मुद्दा है। इसके बगैर विकास के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। शिक्षा में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये। उन्होंने स्कूलों में नामांकन दर में और सुधार की आवश्यकता बताई। मुख्य सचिव श्री जैन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन बुधवार को अधिकारियों को राज्य शासन की प्राथमिकताओं की जानकारी दे रहे थे।

शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर - सत्र में गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी स्कूल भवन की मरम्मत कार्य में शाला विकास समिति और शिक्षा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों की मदद लिये जाने पर बल दिया गया। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिये कि शिक्षा के श्रेष्ठ कौशल रखने वाले शिक्षकों का ग्रुप तैयार कर उनके माध्यम से प्रशिक्षण का निश्चित शेड्यूल तैयार किया जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्रेकिंग का कार्य आंगनवाड़ी से शुरू कर स्कूल की आखरी क्लास तक सतत रखा जाये। अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री संजय दुबे ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के संबंध में जनशिक्षकों की भूमिका पर सुझाव दिये।

ई-अटेंडेंस ऐप का उपयोग - सत्र की शुरूआत में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने बताया कि विकसित मध्यप्रदेश-2047 के प्रमुख बिन्दु में प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता, रोजगारोन्मुखी समावेशी और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना शामिल है। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये सरकारी शिक्षकों के ई-अटेंडेंस ऐप के माध्यम से 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 94 प्रतिशत है। सत्र में बोर्ड परीक्षा परिणाम पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 87 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में और कक्षा 12वीं में करीब 83 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। सचिव महिला एवं बाल विकास सुश्री जी.वी. रश्मि ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी। आंगनवाड़ी में दर्ज 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सिखाने के लिये राष्ट्रीय फ्रेमवर्क आधारशिला तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये नवचेतना फ्रेमवर्क को बनाया गया है। निपुण भारत मिशन में आंगनवाड़ी केन्द्रों में शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला और छात्रावास में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण के लिये सितम्बर 2025 से परख ऐप लांच किया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कक्षा 9 से महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रवृत्ति के लिये केन्द्र सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है।

बेस्ट प्रेक्टिस की दी गई जानकारी - शाजापुर कलेक्टर ने निपुण भारत मिशन के बेस्ट प्रेक्टिस की जानकारी दी। छतरपुर कलेक्टर ने आदर्श आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, कलेक्टर नीमच ने शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और झाबुआ कलेक्टर ने बेस्ट प्रेक्टिस वीडियो परख की प्रस्तुति दी।

सीएस के निर्देश

- विकसित मध्यप्रदेश 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिये नामांकन दर को सुधारने के लिये विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ हो प्रयास।
- सरकारी स्कलों के मरम्मत में शिक्षा में रूचि रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाये।
- बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में परीक्षा परिणाम सुधार के लिये अभी से हो सघन प्रयास।
- सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर मिले, इस पर रखें निगरानी।
- आंगनवाड़ी में पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत हो नामांकन।

जबलपुर के राजस्व अभिलेखागार का नवाचार उपयोगी और अनुकरणीय

● नवीनीकृत अभिलेखागार से रिकॉर्ड की सुरक्षा और सहज उपलब्धता हुई सुनिश्चित ● आयुक्त जनसंपर्क एवं तत्कालीन कलेक्टर जबलपुर सक्सेना ने दिया प्रस्तुतिकरण

भोपाल (नप्र)। कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रथम सत्र में जबलपुर में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम को लेकर हुए नवाचार को उपयोगी तथा अनुकरणीय बताते हुए सराहा गया। इस नवाचार ने जनसामान्य के राजस्व रिकॉर्ड देखने के अनुभव को पूर्णतः बदल दिया है। आयुक्त जनसंपर्क एवं तत्कालीन कलेक्टर जबलपुर श्री दीपक सक्सेना ने लघु फिल्म के प्रस्तुतिकरण में बताया कि जबलपुर के नवीनीकृत राजस्व अभिलेखागार का वातावरण अब बैंक के लॉकर रूम जैसा है। इस पहल से जनसामान्य के साथ रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों को भी गंदे-बदबूदार वातावरण से मुक्ति मिली है और वे रिकॉर्ड ढूंढने की मशक्कत से मुक्त हुए हैं। परिवारों की पीढ़ियों के लिए विशेष महत्व रखने वाला यह राजस्व रिकॉर्ड न केवल अब सुरक्षित है, अपितु रिकार्ड कहां रखा है, इसके संबंध में भी पारदर्शिता आयी है और आवश्यक जानकारियां अब सभी के लिए सुलभ हैं। इसके तैयार किये गये पोर्टल पर चंद एंट्रियों से पता चल जाता है कि रिकॉर्ड किस रैक-शेल्फ-बॉक्स में किस नंबर पर रखा हुआ है। आवेदक घर बैठे भी यह जानकारी प्राप्त कर सकता है और रिकॉर्ड रूम के बाहर लगाए गए कियोस्क से भी रिकार्ड में केस की लोकेशन का पता लगा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर प्रवास के दौरान जनसामान्य के जीवन को आसान बनाने वाले इस नवाचार की सराहना करते हुए जबलपुर जिला प्रशासन को इस पहल के लिए बधाई दी थी।

आयुक्त जनसंपर्क श्री सक्सेना ने बताया कि प्रायः राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम की स्थिति सभी जगह एक समान रहती है। बस्तों में दम तोड़ती फाईलों के बारे में जानकारी प्रायः कुछ बाबुओं और भृत्यों तक सीमित रहती थी। जनसामान्य को अपना ही राजस्व रिकॉर्ड नहीं मिल पाता था। इस स्थिति में बदलाव के लिए रिकॉर्ड रूम को रेनोवेट किया गया। लोहे के रैक्स की मरम्मत कर उनका रंग-रोगन और रिकॉर्ड रखने के लिए कपड़े के बस्ते की जगह प्लास्टिक बॉक्स का उपयोग किया गया। हर केस फाईल को बस्ते से निकालकर प्लास्टिक की पन्नी में रखकर प्लास्टिक बॉक्स में जमाया गया। बॉक्स पर रंगीन स्टीकर की मदद से तहसीलवार कलर कोडिंग की गई। बॉक्स पर वर्षवार, मदवार केस के डिटेल स्टीकर पर प्रिंट कर चिपकाए गए। रैक, शेल्फ, प्लास्टिक बॉक्स और उसमें रखी केस फाईल की लोकेशन के हिसाब से कोडिंग की गई। रैक और उसकी शेल्फ को यूनिक नंबर दिया गया। हर केस फाईल और प्लास्टिक बॉक्स पर लोकेशन का कोड नंबर स्टीकर से चिपकाया गया। केस फाईल की लोकेशन संबंधी सारी जानकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर उस पर डाल दी गई। सुशासन की ओर इस बढ़े कदम से राजस्व रिकॉर्ड के आकांक्षी व्यक्तियों को रिकॉर्ड प्राप्त करने में सरलता और सुगमता की अनुभूति हो रही है।

भोपाल के बड़ा तालाब की हद जानने निकलेंगे 15 पटवारी

कितने मैरिज गार्डन, फैक्टरी, कॉलेज-फार्म हाउस बने जांच में पता चलेगा

भोपाल (नप्र)। भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब की हद जानने के लिए बुधवार को 15 पटवारी निकलेंगे। उनके साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक भी होंगे। सीमांकन में पता लगेगा कि बड़ा तालाब किनारे कितने मैरिज गार्डन, फैक्टरी, कॉलेज, स्कूल, फार्म हाउस या घर बने हैं? इनमें से कितने तालाब की जद में आ रहे हैं। बुधवार से प्रशासन फिर से सीमांकन कार्य शुरू करेगा। बैरागढ़ की तरफ बड़ा तालाब में टीम सीमांकन करने उतरेगी। झील क्षेत्र में जिला व नगर निगम प्रशासन, टीएडंसीपी, वन विभाग की टीम ने कुछ दिन पहले सीमांकन किया था। 3 दिन में रेतघाट से लेकर खानूगांव तक सीमांकन किया जा चुका है। यहां पर कई कब्जे हैं।

नसी में पता चलेगा कि किसका कब्जा- प्रशासन जब नसी करेगा, तब ही पता चल पाएगा कि किसने झील क्षेत्र में मैरिज गार्डन, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, फॉर्म हाउस व घरों का निर्माण किया है। बता दें कि एक बार फिर भोजवैट लैंड के आदेश पर प्रशासन की ओर सीमांकन व नसी की जाएगी। इससे पहले भी सर्वे सीमांकन हुए हैं, लेकिन कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चल सका है।

भैंसाखेड़ी तक सीमांकन होगा - बैरागढ़ तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह ने बताया कि खानूगांव में जिस जगह पर सीमांकन खत्म किया गया था, उसी जगह से जिला प्रशासन, नगर निगम, टीएडंसीपी, वन विभाग के अधिकारी व पटवारियों की टीम सीमांकन शुरू करेगी। बैरागढ़ क्षेत्र में भैंसाखेड़ी तक सीमांकन किया जाएगा।

टीटी नगर, हुजूर, शहर वृत से लगे हिस्से का सीमांकन शुरू नहीं - प्रशासन ने अभी बैरागढ़ इलाके में ही तालाब का सीमांकन करना शुरू किया है। टीटी नगर, हुजूर, शहर वृत एसडीएम ने सीमांकन कार्य शुरू नहीं कराया है। तालाब का क्षेत्र बैरागढ़ के अलावा टीटी नगर, हुजूर, शहर वृत में भी आता है।

एमपी में हैवी रेन का दौर खत्म...अब सिर्फ बूंदाबांदी

● वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव, पर ज्यादा असर नहीं, 3 दिन दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश से हैवी रेन यानी, भारी बारिश का दौर खत्म हो गया है। अब सिर्फ बूंदाबांदी ही होगी। अगले 3 दिन तक दक्षिणी हिस्से के जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या इ. सुरेंद्रन ने बताया कि मानसून की वापसी की परिस्थितियां भी बेहतर हो रही है।

डॉ. सुरेंद्रन ने बताया, प्रदेश के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव रहा। इस वजह से कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई। अगले 24 घंटे के दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। इसके बाद बारिश की एक्टिविटी कम होगी। 9-10 अक्टूबर को कुछ ही जिलों में बूंदाबांदी होने का अनुमान है।

भोपाल में धूप-छांव, इंदौर-जबलपुर में भी ऐसा ही था मौसम - बुधवार को भोपाल में धूप-छांव वाला मौसम रहा। दोपहर तक तेज धूप निकली तो शाम को बादल छा गए। इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसा ही मौसम रहा। शिवपुरी में बूंदाबांदी हुई।

अब फिर वापसी करेगा मानसून - मौसम विभाग के अनुसार, अब तक ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मानसून विदा हो चुका है। राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्से से मानसून विदा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मानसून की वापसी के लिए अब परिस्थिति अनुकूल हो गई है।

बता दें कि इस साल मानसून ने मध्यप्रदेश में 16 जून को दस्तक दी थी। समय से एक दिन बाद मानसून प्रदेश में एंटर हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार, 6 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों से मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस बार वापसी देरी से हो रही है।

गुना में सबसे ज्यादा बारिश - इस बार गुना में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। 65.6 इंच बारिश दर्ज हुई। मंडला-रायसेन में 62 इंच से अधिक और श्योपुर-अशोकनगर में 56 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार सबसे कम बारिश वाले टॉप-5 जिलों में शामिल हैं। शाजापुर में 28.9 इंच, खरगोन में 29.6 इंच, खंडवा में 32 इंच, बड़वानी में 33.5 इंच और धार में 33.6 इंच पानी गिरा है।

मछली परिवार से जुड़े 9 याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत

बैंक खाते डी-फ्रीज करने के आदेश, कोर्ट ने कहा-आरबीआई लिमिट से ज्यादा ना हो कैश विड्रॉल

जबलपुर (नप्र)। यौन उत्पीड़न, ड्रग तस्करी और जमीन पर कब्जे के मामले में फंसे यासीन अहमद मछली के परिवार से जुड़े 9 लोगों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके फ्रीज किए गए बैंक खातों को डी-फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। वहीं मछली परिवार से जुड़े लोगों के घर ढहाने पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं पर कोई अपराध दर्ज नहीं है, तो बैंक खातों को फ्रीज नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक खातों को डी-फ्रीज करते हुए आरबीआई के नियमों के तहत ट्रांजेक्शन किया जा सके। याचिकाकर्ता के खातों से आरबीआई लिमिट से ज्यादा का कैश विड्रॉल ना हो।

आपत्तिजनक सामग्री मिले तो कार्रवाई को स्वतंत्र पुलिस - जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि परिवार के सीनियर सदस्यों के बैंक खाते डी-फ्रीज किए जाएं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है। पुलिस जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है।

बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुरक्षित रखे फैसले को सार्वजनिक करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। दरअसल, भोपाल के गैंगस्टर यासीन अहमद उर्फ मछली के पारिवारिक सदस्यों की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने मकान तोड़ने की कार्रवाई, बैंक खाते फ्रीज करना, हथियार के लाइसेंस को कैंसिल करना और ईमेल को ब्लॉक करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

अधिकारियों ने स्वीकार किया क्रिमिनल केस नहीं - जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने 26 सितंबर को याचिका की सुनवाई करते भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अखिल पटेल को गवाही के लिए बुलाया था। तब दोनों अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि आरोपी के खाते से पिटीशनर के अकाउंट में एक बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसकी जांच पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले पर भोपाल पुलिस अपनी जांच को जारी रखे साथ ही मछली परिवार से जुड़े लोगों के घर ढहाने पर सरकार विस्तृत जवाब दे।

याचिकाकर्ता ने कहा-संपत्ति को नुकसान पहुंचाया - मछली परिवार की साजिदा-बी के साथ 9 अन्य सदस्यों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया था कि सरकार ने कार्रवाई के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिसे लेकर यह याचिका दायर की गई है। भोपाल के आनंदपुरा में रहने वाली साजिदा बी एवं अन्य 7 लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया गया कि उनके नाम एफआईआर में नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई अपराधी की जांच चल रही है। इसके बावजूद भी यासीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही उनकी संपत्ति तोड़ी गई, बैंक खाता भी फ्रीज किए गए। यहां तक कि उनके ईमेल भी ब्लॉक कर दिए गए।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त नहीं हैं, फिर भी उनके घरों को तोड़ा गया। 21 अगस्त 2025 को जब प्रशासन ने संपत्ति ध्वस्त करने को लेकर कार्रवाई की थी तो कोई भी वैद्य नोटिस या उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अन्य सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें ही निशाना बनाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बिना अभियोग के घरों को तोड़ना, बैंक खाता सीज करना और हथियार लाइसेंस निलंबित करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है।

संपादकीय

बिहार : नीतीश का भविष्य दांव पर

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों प्रमुख महागठबंधनों की सेनाएं आमने-सामने हैं, हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों में घमासान मचा है। ये चुनाव बिहार में जहां नीतीश कुमार का भविष्य तय करेगा, वहीं तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अरमान कहां तक पूरे होंगे, यह भी तय करेगा। यह भी निर्धारित होगा कि वोट चोरी और नीतीश के बुढ़ापे के मुद्दे को जनता तवज्जो देगी या फिर चुनाव से पहले एनडीए सरकार द्वारा बांटी गई रेवड़ियां सब पर भारी पड़ेगी और यह भी कि क्या बिहार में जातिवाद से इतर कोई राजनीति इस बार हावी होगी या जैसे चलता रहा है, वैसे ही चलेगा। गौरतलब है कि इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने दो चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। ये मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नंवबर को समाप्त हो रहा है। यानी चुनाव आयोग सारी प्रक्रिया इसके पहले ही पूरी कर लेगा। राजनीतिक पार्टियों की मांग पर चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा लंबा नहीं खींचा गया है। साथ ही त्यौहारों का भी ध्यान रखा गया है। सभी की निगाह इस बात पर है कि बिहार में आखिर होगा क्या? क्योंकि राज्य में नीतीश कुमार विगत 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। इस बीच वो दो बार पाला बदल चुके हैं। लेकिन नीतीश का अति पिछड़ा वोट इतना मजबूत है कि दूसरे दल उसे चाहकर भी नहीं हिला सके हैं। महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश के सुशासन और विकास के नैरेटिव को तोड़ना है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर युवा ईबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। हालांकि, 'जंगल राज' की वापसी का डर, खासकर उच्च जाति और कुछ ईबीसी मतदाताओं के बीच, महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा, कांग्रेस का बिहार में सीमित जनाधार एक बड़ी बाधा है। कांग्रेस को इस वर्ग के बीच अपनी पुरानी साख वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस और महागठबंधन ने 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प' पत्र जारी कर बिहार में नयी सियासी हलचल पैदा कर दी है। महागठबंधन के इस फ़ैसले को उस अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है जो नीतीश कुमार का मज़बूत वोट बैंक रहा है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग का 36 प्रतिशत वोट बैंक है। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजबूत आधार माना जाता है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह संकल्प पत्र नीतीश के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? अब नीतीश पांचवीं बार सीएम बनेंगे या उन्हें कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, वो स्वयं कुर्सी छोड़कर इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, यह अभी कहना मुश्किल है। हालांकि नीतीश द्वारा अपने पुत्र को राजनीति में लाने के पीछे संकेत यह देखा जा रहा है कि वो चुनाव जीतने पर अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंप सकते हैं। लेकिन यह अभी दूर की कौड़ी है। बिहार में आज भी सबसे बड़ा मुद्दा खुद नीतीश कुमार ही हैं। उन्हें माइनस करके कोई भी गठबंधन सत्ता में आने का ख्वाब नहीं देख सकता। भाजपा के लिए तो नीतीश की गरज दिल्ली की सत्ता टिकाए रखने की दृष्टि से भी है। क्योंकि मोदी सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी है, उनमें से एक नीतीश कुमार की जद यू है। दूसरे, इस चुनाव में दो गठबंधन की ताकतें भी अहम हैं। एक हैं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और दूसरे हैं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी तो महागठबंधन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। यदि उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया तो वो राज्य के मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दलित प्रताड़ना- बिहार को मिला नया चुनावी मुद्दा

अब सवाल यह है कि ये दोनों घटनाएं बिहार चुनाव में कैसे मुद्दा बन रही हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। दो चरणों में वोटिंग होगी- 6 नवंबर और 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यहां दलित वोटरों की संख्या करीब 16-19 प्रतिशत है, जो चुनावी नतीजों को पलट सकती है। कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं को अपनी रणनीति का हिस्सा बना रही है। पार्टी की थीम है- दलित गरीब हो या सीजेआई, भाजपा राज में ये निशाने पर, संविधान-लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस ने बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बनाया है, जो काफी पहले से तैयारी का हिस्सा है। राहुल गांधी हर सभा में दलित मुद्दों को उठा रहे हैं। वह संविधान पर हमले, आरक्षण और जाति जनगणना की बात करते हैं।

बिहार के चुनावी मौसम में इस बार हवा कुछ अलग बह रही है। जहां एक तरफ विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की बातें जोर पकड़ रही हैं, वहीं रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की घटना अब बिहार विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं को हाथों-हाथ लेकर दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं, बल्कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचारों का जीता-जागता सबूत हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली की उस दर्दनाक घटना की, जो पूरे देश को झकझोर रही है। 2 अक्टूबर 2025 को रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को गांव वालों ने चोरी के शक में इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। हरिओम अपनी ससुराल ईश्वरदासपुर आया था, लेकिन गांव वालों ने उसे ड्रोन चोर समझ लिया। दो घंटे तक लाठी-डंडों, बेल्ट और लात-घूंसों से पिटाई होती रही। हरिओम कराहते हुए बार-बार 'राहुल गांधी-राहुल गांधी' का नाम ले रहा था, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। हैरानी की बात यह है कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हरिओम को अस्पताल ले जाने की बजाय गांव वालों के हवाले छोड़ दिया। हरिओम की पत्नी का कहना है कि पुलिस ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। किसी ने इस पूरी घटना के तीन वीडियो बना लिए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। वीडियो में हरिओम की चीखें और उसकी आखिरी सांसें साफ सुनाई दे रही हैं, जो किसी भी इंसान का कलेजा चीर सकती हैं। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का आरोप है कि असली दोषी अब भी आजाद घूम रहे हैं। हरिओम के पिता गंगादीन ने बताया कि उनका बेटा मजदूरी करता था और परिवार की कमर टूट गई है। इस घटना ने एक बार फिर मॉब लिंचिंग के पुराने घावों को कुरेद दिया है, जहां दलित और कमजोर वर्ग के लोग आसानी से निशाना बन जाते हैं। कांग्रेस ने इसे समाज पर कलंक बताया और भाजपा सरकार पर सवाल उठाए कि क्या यूपी में जंगलराज चल रहा है?

वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने तुरंत हरिओम के परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और अपने एक्स हैंडल पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। राहुल ने लिखा, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं- इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब- हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं- उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल की यह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और दलित समुदाय में काफी सराही जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जो खुद दलित समुदाय से हैं, ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग और बुलडोजर अन्याय आज की भयावह हकीकत बन गए हैं। खरगे और राहुल ने संयुक्त बयान में इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार से नौकरी और मुआवजे की मांग की। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम जैसे नेता भी परिवार से मिले और बोले कि भाजपा में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। यह घटना फतेहपुर के दलित समाज में आक्रोश पैदा कर रही है, जहां हरिओम को राहुल का नाम लेने पर और पीटा गया।

इस घटना के ठीक बाद, 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक और चौंकाने वाली वारदात हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, पर 71 साल के वकील राकेश किशोर ने जूता उछाल दिया। राकेश बरेली का रहने वाला है और खुद को सनातन धर्म का रक्षक बताता है। वह कहता है कि सीजेआई की एक पुरानी टिप्पणी से आहत था। दरअसल, 16 सितंबर को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति को लेकर याचिकाकर्ता से मजाक में कहा था कि मूर्ति से प्रार्थना करो, शायद वह अपना सिर वापस लगा ले। राकेश ने इसे सनातन धर्म का अपमान माना और कोर्ट में ही जूता फेंक दिया। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। राकेश ने बाद में कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं, ये सब ऊपर वाले ने कराया। मैं सनातन का अपमान सहन नहीं कर सकता। हैरानी की बात यह है कि राकेश पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। चीफ जस्टिस गवई ने खुद इसे अनदेखा करने को कहा और बोले, इसे अनदेखा कर दीजिए, मैं इससे विचलित नहीं होने वाला। लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना ने तूफान मचा दिया। कुछ लोग इसे दलितों के खिलाफ नफरत का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ इसे न्यायपालिका पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस गवई से फोन पर बात की और घटना पर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने भी निंदा की। विपक्षी नेता जैसे अखिलेश यादव और संजय राउत ने इसे भाजपा की साजिश बताया और कहा कि यह संविधान पर हमला है। राकेश का बयान कि दूसरे समुदाय के जज सनातन का मजाक उड़ाते हैं ने दलित समाज को और भड़का दिया है।

अब सवाल यह है कि ये दोनों घटनाएं बिहार चुनाव में कैसे मुद्दा बन रही हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। दो चरणों में वोटिंग होगी- 6 नवंबर और 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यहां दलित वोटरों की संख्या करीब 16-19 प्रतिशत है, जो चुनावी नतीजों को पलट सकती है। कांग्रेस पार्टी इन घटनाओं को अपनी रणनीति का हिस्सा बना रही है। पार्टी की थीम है- दलित गरीब हो या सीजेआई, भाजपा राज में ये निशाने पर, संविधान-लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस ने बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को बनाया है, जो काफी पहले से तैयारी का हिस्सा है। राहुल गांधी हर सभा में दलित मुद्दों को उठा रहे हैं। वह संविधान पर हमले, आरक्षण और जाति जनगणना की बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने नालंदा और गया में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, जहां सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी। राहुल ने सरकारी नौकरियों और ठेकों में ईबीसी आरक्षण का दांव चला, जो बिहार के पिछड़ों को लुभा रहा है। कांग्रेस महागठबंधन में 55 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, जहां राजद के साथ सीट बंटारे पर मुहर लग चुकी है। पार्टी सीमांचल इलाके पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम और दलित वोटर ज्यादा हैं।

बिहार में दलित वोटरों का इतिहास देखें तो वे कभी एकमुश्त किसी पार्टी को नहीं जाते। रविदास और पासवान जातियां प्रमुख हैं। एनडीए में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा-जदयू सरकार में दलित अत्याचार बढ़े हैं। चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। कई जगह जिंदा दलितों को मृत दिखाया गया है, जबकि मृतकों को जिंदा। कांग्रेस का दावा है कि यह गरीब-दलितों के वोट चुराने की साजिश है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा ने 23 जिलों में वोट चोरी को मुद्दा बनाया। विपक्षी पार्टियां जैसे राजद और सीपीआईएमएल भी दलितों पर फोकस कर रही हैं। सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि बिहार में दलित बस्तियों में आग लगाकर बेदखली हो रही है, मजदूरों के हाथ काटे जा रहे हैं। पिछले 20 साल की सरकार में बेरोजगारी और पलायन चरम पर है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी नए विकल्प के रूप में उभर रही है, लेकिन राहुल और तेजस्वी का भरोसा दलितों को अपनी ओर खींच रहा है।ये मुद्दे चुनाव को नया मोड़ दे सकते हैं। जहां भाजपा विकास और मोदी-योगी की छवि पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस दलितों की भावनाओं को भुनाने की कोशिश में है। रायबरेली और सीजेआई घटना ने दलितों में गुस्सा भरा है, जो बिहार में वोट बन सकता है। अगर कांग्रेस सफल हुई, तो यह न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। अंत में, सवाल यही है- क्या संविधान और न्याय की लड़ाई चुनावी जीत दिलाएगी या विकास की बातें हावी रहेंगी? बिहार के मतदाता ही फैसला करेंगे।

सेहत

राज कुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

मीठे कफ सिरप का जहरीला कारोबार

यूनिसेफ़ ने अपने बाल स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों में कहा है कि कफ सिरप बच्चों के उपचार में अनुशंसित नहीं हैं। इसके स्थान पर गुनगुने तरल पदार्थ, एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शहद, और लक्षणों की निगरानी जैसी सुरक्षित विधियों की सलाह दी गई है। भारत में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) भी चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कफ सिरप के नियमित उपयोग के विरुद्ध सलाह देती है, यह कहते हुए कि इसकी प्रभावशीलता का कोई प्रमाण नहीं है और यह बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब आवश्यक है कि औषधि नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। दवाओं के निर्माण, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर कड़ी निगरानी तत्काल सुनिश्चित की जाए।

मध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या 16 हो गयी है। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर और सीकर जिले में भी बच्चों को कफ सिरप पिलाने से मौत हुई है। बच्चों को दिए गए सिरप में डाय-एथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) एवं एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) जैसे कूलेंट (ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ) के लिए उपयोग होने वाले घातक रसायन पाए गए हैं, जो अत्यंत विषैले हैं। यह गुर्दे, लीवर और मस्तिष्क पर घातक असर डालता है। दवाओं में इनका प्रयोग पूर्णतः गैरकानूनी है। डीईजी ग्लिसरीन में पाया जाने वाला सबसे आम संदूषक (कंटेमीनेशन) है। इसमें ग्लिसरीन की तरह ही गाढ़ा करने और आराम देने वाले गुण होते हैं। डीईजी एक औद्योगिक विलायक (सोल्वेंट) है जिसका उपयोग 'एंटीफ्रीज़ और पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में' किया जाता है। कंपनियां कभी-कभी तरल दवाओं, जैसे कि कफ सिरप, में अवैध मिलावट के रूप में डीईजी का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यह ग्लिसरीन जैसे गैर-विषैले विलायकों का एक सस्ता विकल्प है। संदूषण के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जानबूझकर मिलावट किया जाता है। मेडिसिन के जानकार डाक्टर अनंत फडके, पुणे बताते हैं कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश कफ सिरप अविवेकपूर्ण (इरेशनल) हैं, परंतु कुछ कफ सिरप अविवेकपूर्ण नहीं हैं। अविवेकपूर्ण कफ सिरप वे होते हैं जिनमें एक साथ दो परस्पर विरोधी तत्व मिलाए जाते हैं। एक कफ दबाने वाला पदार्थ और दूसरा बलगम निकालने वाला जो एक-दूसरे के कार्य को निष्फल कर देते हैं। इनके साथ अक्सर कुछ बेकार या अप्रभावी तत्व भी मिलाए जाते हैं। यदि किसी कफ सिरप में केवल एम्ब्रोक्सोल हो, तो वह अविवेकपूर्ण कफ सिरप नहीं माना जाता। हाल के वर्षों में भारत के कई राज्यों में विशेषतः मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और बिहार में कफ सिरप के दुरुपयोग व काला कारोबार के मामले तेजी से बढ़े हैं।कफ सिरप का काला कारोबार केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल है। यह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है बल्कि दवा नियमन, कानून और उद्योग एवं प्रशासन तीनों की नैतिक विफलता का संकेत भी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी.नड्डा ने एडवाइजरी किया है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप (खांसी की दवा) नहीं दी जानी चाहिए, और दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप दी जाए। यह बाल स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है।जन स्वास्थ्य अभियान, इंडिया के अमुल्य निधि ने कहा कि हाथी समिति रिपोर्ट (1975) ने अनुशंसा की थी कि अविवेकपूर्ण और अनावश्यक औषधि संयोजन, जैसे कि कफ सिरप, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। समिति ने स्पष्ट कहा था कि कफ सिरप का कोई सिद्ध चिकित्सीय लाभ नहीं है और इससे प्रतिकूल प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है।

2022 में, कई देशों ने बच्चों के लिए ओवर-द-काउंटर कफ सिरप के डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) के विषाक्त स्तर से दूषित होने की घटनाओं की सूचना दी थी, जिसके परिणामस्वरूप गाम्बिया, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान में 300 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रभावित देशों में इन घटनाओं से निपटने के लिए 2022 के अंत तक और 2023 के मध्य

तक 5 चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किए थे । इंडोनेशिया में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 144 बच्चों की मौत के बाद कुछ कफ सिरप-आधारित दवाओं की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी थी ।विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार-बार कहा है कि खांसी और सर्दी की दवाएं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उपयोग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत कम होता है और गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

यूनिसेफ़ ने अपने बाल स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों में कहा है कि कफ सिरप बच्चों के उपचार में अनुशंसित नहीं हैं। इसके स्थान पर गुनगुने तरल पदार्थ, एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शहद, और लक्षणों की निगरानी जैसी सुरक्षित विधियों की सलाह दी गई है।भारत में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) भी चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कफ सिरप के नियमित उपयोग के विरुद्ध सलाह देती है, यह कहते हुए कि इसकी प्रभावशीलता का कोई प्रमाण नहीं है और यह बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।अब आवश्यक है कि औषधि नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। दवाओं के निर्माण, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर कड़ी निगरानी तत्काल सुनिश्चित की जाए। मशेलकर समिति (2004) की सिफारिश के अनुसार, औषधि प्रशासन (एफडीए) को सुदृढ़ किया जाए। पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए और उनकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी व जवाबदेह बनाया जाए।जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मांग किया है कि सरकारी आपूर्ति श्रृंखलाओं (राज्य स्वास्थ्य विभागों और केंद्रीय एजेंसियों) से सभी कफ सिरप को तुरंत हटाया जाए।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार निर्माताओं और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इन घटनाओं ने दिखाया है कि राज्य और केंद्र के ड्रग कंट्रोलर तंत्र में निगरानी की गंभीर कमी है। यदि नियमित सैंपल टेस्टिंग, निरीक्षण और 'ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम' ठीक से लागू होते, तो ऐसी त्रासदी टाली जा सकती थी। जबकि 'ड्रग कंट्रोलर' अधिकारी का पद भारत में दवाओं की गुणवत्ता, विनियमन, निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। जिसमें यदि कोई शिकायत आती है कि किसी दवा में अशुद्धियां या विषाक्तता हो सकती है, तो तुरन्त उस दवा के सैंपल लेना, दवा को बाजार से हटाने की कार्रवाई करना।जिम्मेदारों (निर्माता, वितरक, विक्रेता) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना।यदि किसी दवा की गुणवत्ता मानकों को पूरा न करती हो या वह जोखिमपूर्ण पाई जाए, तो उससे संबंधित लाइसेंस रद्द करना, या उस दवा के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर के ड्रग कंट्रोलर 'राजाराम शर्मा' को निलंबित कर दिया है। यह संकेत है कि प्रशासन ने मान लिया कि ड्रग कंट्रोलर की कार्यप्रणाली में गंभीर चूक हुई है।

केवल दवा कंपनी को दोषी ठहराना पर्याप्त नहीं है। निरीक्षण अधिकारियों, आपूर्ति अधिकारियों, और नियामक निकायों की भी जवाबदेही तय करनी होगी। 'सिस्टम की चूक' पर संस्थागत जवाबदेही तय की जाए, ताकि अगली बार कोई अधिकारी निरीक्षण में लापरवाही न करे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

शांतिलाल जैन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जहाँ फुटपाथ, वहीं बाजार; जहाँ बाजार, वहीं जीवन, वहीं सभ्यता

सन् 2525 ई. में आर्यावर्त में व्यापार संवर्धन में फुटपाथ का योगदान विषय पर लिखे जाने वाले काल्पनिक शोधप्रबंध का संक्षिप्त अंश- बीसवीं के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्ध में आर्यावर्त में व्यापार फुटपाथ किनारे विकसित हुआ। नगरीय सभ्यता के विकास में जितना महत्व नदियों का रहा आया, व्यापार के विकास में उतना ही महत्व फुटपाथ का रहा आया। 'आर्यावर्त में व्यवसाय संस्कृति फुटपाथ किनारे विकसित हुई' यह कथन केवल नगरपालिका द्वारा निर्मित एक भौगोलिक सत्य नहीं था, बल्कि एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता भी थी। यदि हम उस समय की नागर सभ्यता पर दृष्टि डालें, तो पाएंगे कि अधिकांश बाज़ार फुटपाथ अतिक्रमित दुकानों पर पनपे। भोपाल का न्यू-मार्केट, दिल्ली का चांदनी चौक, मुंबई का कोलाबा कॉजवे, जयपुर का बापू बाज़ार आदि अनेक बाज़ार फुटपाथ किनारे विकसित हुए. यहाँ कपड़ों, जूते-चप्पलों, स्ट्रीट फूड, मोबाइल फोन्स, तोते वाले ज्योतिष और सॉफ्ट-पोर्न लिटरेचर तक के करोड़ों के व्यापार पनपने के प्रमाण मिले हैं।

अनुमान है कि नगर नियोजकों की योजना में फुटपाथ पैदल चलने वालों को वाहन दुर्घटना से बचाववाला रास्ता प्रदान करने की रही होगी, मगर व्यवसाय संवर्धन की छुपी संभावनाओं ने उसे शॉपिंग पाथ-वे में बदल दिया होगा। उन पर नागरिक उतने कदम ही चल पाते जितने एक काऊंटर से दूसरे तक पहुँचने के लिए जरूरी होते। फिर डिस्प्ले के सामानों, होर्डिंग्स, स्टेंडिज़, डिझाईनर साड़ी, जींस, टीशर्ट पहने मनेक्वीन पुतलों ने पथिक को फुटपाथ से बेदखल कर दिया। कमाने के अवसर फुटपाथ ने व्यवसायियों को ही नहीं दिए, उसने ट्रैफिक पुलिस और मुन्सीपाल्टी के मुलाज़िमों को भी संपन्न बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वे जेबें ठंडी लेकर आते और गरम करके ले जाते।

नदियों की तरह फुटपाथ भी मनुष्य के लिए जीवनरेखा जैसे थे। वे जीने के लिए आवश्यक पोषक आहार यथा पोहा, कचोरी, समोसे, कटिंग चाय की सतत आपूर्ति किया करते थे। आम नागरिक फुटपाथ पर डलीं चेयर्स पर इत्मिनान से बैठकर इडली-डोसा, पावभाजी-आलू-टिकिया खाया करते तो पढ़े-लिखे नागरिक दोने-प्लेट-डिस्पोजेबल वहीं फेंक दिया करते। वे वहाँ बैठकर रील देखते, चुहल करते, सेल्फी लिया करते थे। 'पार्टी ऑन पेवमेंट' का चलन आम था। अंकल-आंटी केक काटकर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लिया करते। जेन-ज़ी यहीं सॉफ्ट अभिसार कर लेती, एकांत ढूंढने की गरज़ रही नहीं। कहीं कहीं फुटपाथ के नीचे बहते नाले बजबजाने लगते। इनसे उपजी बदबू का सामना करने के लिए लोग घर से ही बगल में डियोडोरेंट लगाकर आते।

प्रारंभिक दौर के फुटपाथ सीमेंट कांक्रीट के हुआ करते थे, बाद के दौर में उनके पेविंग ब्लॉक से बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। दुकानदार यहीं से उखाड़कर एक ब्लॉक डगमगाते काऊंटर के टूटे हुए पाए के स्थान पर लगाकर संतुलन बना लिया करते। समझा जाता है कि कुछ सभ्य, संपन्न नागरिक उखड़े पेवमेंट से उठाकर एक दो ब्लॉक कार की डिक्की में रख लिया करते थे कि हेंड-ब्रेक खराब होने की दशा में पहिये पर रोक लगाकर कार को लुढ़कने से बचाया जा सके। फुटपाथ जिस खुले-मन से नागरिकों को मार्केट-प्लेस मुहैया कराते उसी भावना से चौपायों को आशियाना भी प्रोवाईड करते। फुटपाथों पर चौपाये यथासमय सौ मीटर स्प्रिंट, हर्डल-रेस, हाय-जम्प, लांग-जम्प आदि के आयोजन करते रहते। नागरिक अपने वाहन फुटपाथ पर ही खड़े कर लिया करते इससे पालिकाओं को पार्किंग लॉट बनाने नहीं पड़े।

फुटपाथ ने मनुष्यता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से किया। दुकानों में काम करनेवाले प्रवासी मजदूर दिन भर जिस फुटपाथ पर माल बेचा करते, रात को उसी पर अखबार बिछाकर सो जाते। इससे यमदूतों को बहुत सुविधा रहती। वे भैंसे पर बैठकर आने के बजाए बीएमडब्ल्यू कार से आते और सोए हुए गरीबों के शरीर से आत्मा निकालकर ले जाते। फ्रॉम फुटपाथ टू बैकुंठ, डायरेक्ट।

सभ्यता के विकास में सामाजिक समरसता के महत्व को पहचानते हुए फुटपाथों ने शनि मंदिर के लिए भी स्पेस प्रोवाईड किया और सखी-पीर की मजार के लिए भी। कुछ नागरिक यहाँ खड़े रहकर महाआरती करते, कुछ नमाज़ पढ़ते। हार-फूल-तेल-नारियल-लोभान का व्यवसाय खूब फला-फूला। इससे न केवल पुजारियों और खादिमों में सम्पन्नता बढ़ी बल्कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का आपसी संपर्क भी बढ़ा। आर्यावर्त में फुटपाथ ही था जो सही मायने में धर्मनिरपेक्ष आचरण कर पाता था। कुछ स्थानों पर तो फुटपाथों ने अपना वजूद मिटाकर भी धर्मस्थलों को पनपने दिया। इस प्रकार आर्यावर्त में उस दौर में बाज़ार, फुटपाथ और मानव के बीच गहरे और अपरिहार्य संबंध के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन कहीं-कोई फुटपाथ महज़ पैदल चलने के उपयोग में आया हो इसके प्रमाण नहीं मिले। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि आर्यावर्त में सभ्यता की जड़ें पाँच सौ साल पुराने फुटपाथों के किनारे बसी हैं।

विश्व डाक दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं।

259 वर्ष पुराना है भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास

9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके फलस्वरूप 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' की स्थापना हुई। इस संगठन ने वैश्विक डाक व्यवस्था को एकीकृत स्वरूप दिया, जिसके बाद दुनिया के किसी भी कोने से भेजा गया पत्र समान नियमों और व्यवस्थाओं के तहत किसी अन्य देश में पहुंचना संभव हुआ। भारत ने 1 जुलाई 1876 को इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की और इस प्रकार वह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना। 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित विश्व डाक संघ सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष 'विश्व डाक दिवस' के रूप में मनाया जाएगा ताकि डाक सेवा के महत्व, उसकी भूमिका और इसके नवाचारों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके।

प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को 'विश्व डाक दिवस' मनाया जाता है, जो दुनिया को जोड़ने वाले सबसे पुराने और विश्वसनीय संचार तंत्र की याद दिलाता है। आज के डिजिटल युग में जब संदेश चंद सैकेंड में ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, ऐसे में डाक सेवा का इतिहास न केवल तकनीकी विकास की कहानी है बल्कि मानव सभ्यता की उस यात्रा का साक्षी है, जिसने संवाद को संस्कृति, भावना और विश्वास के स्तर तक पहुंचाया। डाक केवल पत्र नहीं पहुंचाता, वह रिश्तों, संवेदनाओं और इतिहास को भी एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाने का साधन रहा है।

9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके फलस्वरूप 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' की स्थापना हुई। इस संगठन ने वैश्विक डाक व्यवस्था को एकीकृत स्वरूप दिया, जिसके बाद दुनिया के किसी भी कोने से भेजा गया पत्र समान नियमों और व्यवस्थाओं के तहत किसी अन्य देश में पहुंचना संभव हुआ। भारत ने 1 जुलाई 1876 को इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की और इस प्रकार वह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना। 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित विश्व डाक संघ सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष 'विश्व डाक दिवस' के रूप में मनाया जाएगा ताकि डाक सेवा के महत्व, उसकी भूमिका और इसके नवाचारों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके।

भारत की बात करें तो यहां डाक व्यवस्था का इतिहास 259 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने भारत में डाक सेवा की नींव रखी। उस समय यह व्यवस्था मुख्यत: प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। उसके बाद 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने भारत का पहला डाकघर कोलकाता में स्थापित किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1786 में चेन्नई और 1793 में मुंबई में जनरल पोस्ट ऑफिस स्थापित किए गए, जो उस दौर में अंग्रेजी शासन के तहत संचार व्यवस्था की रीढ़ बने। धीरे-धीरे यह व्यवस्था आम नागरिकों तक पहुंची और जन-संचार का माध्यम बनी। डाक टिकटों का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है, जितना डाक व्यवस्था का। डाक टिकटों की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में 1852 में सिंध प्रांत में हुई, जब वहां के तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन ने एक सीमित प्रयोग के तौर पर टिकटें जारी की। ये टिकट केवल सिंध प्रांत के भीतर ही मान्य थी। पूरे भारत के लिए पहला आधिकारिक डाक टिकट 1854 में जारी हुआ लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो डाक टिकटों का इतिहास करीब 185 वर्ष पुराना है। डाक टिकट का विचार एक ऐसी समस्या के समाधान से जन्मा, जो आज के संदर्भ में बेहद साधारण प्रतीत होती है पर उस समय सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। 18वीं सदी तक डाक प्रेषण का शुल्क या तो पत्र भेजने वाले को देना पड़ता था या पत्र प्राप्त करने वाले से वसूला जाता था। अक्सर ऐसा होता कि पत्र भेजने वाला शुल्क चुकाए बिना ही पत्र भेज देता और प्राप्तकर्ता उसे लेने से इंकार कर देता। इससे डाक विभाग को भारी आर्थिक नुकसान होता था। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक सलाहकार सर रोलैंड हिल ने इस समस्या का स्थायी समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि पत्र भेजने वाले को अग्रिम रूप से शुल्क देना चाहिए और इसका प्रमाण एक मुद्रित टिकट के रूप में होना चाहिए। इस तरह अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करने का विचार जन्मा और डाक टिकट की अवधारणा विकसित हुई।

ब्रिटिश सरकार ने हिल के इस सुझाव को स्वीकार किया और 10 जनवरी 1840 को पहला डाक टिकट तैयार किया गया। यह टिकट आधिकारिक रूप से 6 मई 1840 को जारी हुआ, जिसे 'ब्लैक पैनी' नाम दिया गया क्योंकि यह काले रंग की स्याही से छापा गया था और इसका मूल्य एक पैनी था। यही विश्व का पहला डाक टिकट बना। इसके जारी होने से डाक प्रणाली में पारदर्शिता आई और डाक विभाग को अनावश्यक घाटे से मुक्ति मिली। आधा औंस वजन तक के पत्र के लिए एक पैनी और एक औंस तक के लिए दो पैनी का शुल्क निर्धारित किया गया। ब्लैक पैनी की सफलता के बाद डाक टिकटों का उपयोग तेजी से विश्वभर में फैल गया। ब्राजील ने 1843 में, अमेरिका ने 1847 में, बेल्जियम ने 1849 में और भारत ने 1854 में अपने पहले डाक टिकट जारी किए। उस समय डाक टिकट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था बल्कि राष्ट्र की पहचान, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी था।

यही कारण है कि हर देश ने अपने टिकटों पर अपने नायकों, स्मारकों, प्राकृतिक धरोहरों और वैज्ञानिक उपलब्धियों को स्थान दिया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के कई ऐतिहासिक क्षण डाक टिकटों के माध्यम से अमर किए गए हैं। प्राचीन काल में, जब डाक व्यवस्था का औपचारिक स्वरूप नहीं था, तब राजा-महाराजा अपने संदेश दूतों या प्रशिक्षित पक्षियों के माध्यम से भिजवाया करते थे। कबूतरों, घोड़ों और अन्य पशुओं का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में होता था। ये संदेशवाहक राजाओं के गुप्त आदेशों, युद्ध-संदेशों और प्रेम-पत्रों तक को पहुंचाते थे। समय के साथ डाक ने न केवल शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति की बल्कि आम जनता के जीवन में भी भावनाओं का वाहक बन गई।

डाक टिकटों का संग्रह, जिसे 'फिलेटली' कहा जाता है, आज भी लाखों लोगों की रुचि का विषय है। डाक टिकटों के संग्राहक केवल पुराने टिकटों को इकट्ठा नहीं करते बल्कि वे हर टिकट के पीछे छिपे इतिहास, भूगोल और संस्कृति की कहानी भी समझते हैं। कुछ लोग इस जुनून को इतना आगे ले गए कि उन्होंने दुनिया के सबसे दुर्लभ टिकटों का संग्रह कर लिया। अमेरिका के जेम्स रूक्सिन के पास विश्व के लगभग सभी दुर्लभ टिकटों का संग्रह है, जिसमें 'ब्लैक पैनी' से लेकर आधुनिक टिकटों तक की श्रृंखला शामिल है। बताया जाता है कि उनके संग्रह में 40 हजार से अधिक टिकट हैं। पुराने और दुर्लभ टिकटों की कीमत आज लाखों डॉलर तक पहुंच जाती है। भारत में भी फिलेटली का शौक तेजी से बढ़ा है। भारतीय डाक विभाग समय-समय पर विशेष अवसरों पर स्मारक डाक टिकट जारी करता है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वतंत्रता संग्राम, खेलकूद, विज्ञान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासतों पर आधारित टिकटें। ये न केवल संग्रहणीय वस्तुएं हैं बल्कि देश की ऐतिहासिक स्मृतियों का सजीव दस्तावेज भी हैं।

आज जब तकनीक ने दुनिया को स्मार्टफोन और ईमेल के युग में ला खड़ा किया है, तब भी डाक सेवाओं का महत्व कम नहीं हुआ। भारत में डाक विभाग ने खुद को नए युग की जरूरतों के अनुसार बदला है। अब डाकघरों में केवल पत्र नहीं बल्कि बैंकिंग, बीमा, ई-कॉमर्स पार्सल, डिजिटल भुगतान और ग्रामीण संचार जैसी आधुनिक सेवाएं भी दी जा रही हैं। भारतीय डाक सेवा देश के सबसे व्यापक नेटवर्कों में से एक है, जिसके लगभग 1.6 लाख से अधिक डाकघर हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण भारत में हैं। यह केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

विश्व डाक दिवस हमें स्मरण कराता है कि संचार की आत्मा केवल गति नहीं बल्कि विश्वसनीयता और मानवीय जुड़ाव है। पत्र चाहे कागज पर लिखा हो या डिजिटल माध्यम से भेजा जाए, उसकी भावना वही रहती है।

डाक सेवाएं आज भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, जिसने रिश्तों को जोड़ा, देशों को नजदीक लाया और इतिहास को सहेजा। डाक टिकट की यात्रा 'ब्लैक पैनी' से लेकर आज के डिजिटल बारकोडेड टिकटों तक, मानव सभ्यता की उस जिज्ञासा का परिणाम है, जिसने हर युग में संवाद को सरल और सुलभ बनाया। यह केवल डाक का नहीं बल्कि मानवीय अभिव्यक्ति का उत्सव है, जो हमें जोड़ता है, याद दिलाता है और बताता है कि चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक पत्र की गर्माहट कभी पुरानी नहीं पड़ती।

विचार

विवेक कुमार मिश्र

लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

जिंदगी की कहानी कहते हैं दाने और छिलके

बातें करते जाइए और मूंगफली का आनंद लेते जाइए, गीली मूंगफली का स्वाद ही अलग होता है, मूंगफली सिक रही हो और खाने का मन न करें ऐसा हो ही नहीं सकता, अक्सर हम सबके अनुभव में बस स्टैंड पर खड़ी बस के साथ मुंगफली लेने और रास्ते भर मूंगफली को खाने का अनुभव और आनंद जुड़ा रहता है। बहुत बार लोग मूंगफली के साथ साथ उसके छिलके भी खा जाते हैं इस तर्क के साथ की कुछ भी बेकार नहीं जाना चाहिए। पर मूंगफली के दाने ही सब खाते हैं छिलके को चबाने वाले अपवाद हो सकते हैं पर छिलके भी कभी कभी समय पास करने के क्रम में मुंह में आ ही जाते हैं। मूंगफली हो और मूंगफली के साथ मसालेदार नमक और चटनी हो फिर थोड़ा नमक और मूंगफली का स्वाद लेते हुए मूंगफली खाने का आनंद ही कुछ और है। मूंगफली जब खाते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है उसका छिलका उतारकर ही खा सकते हैं ऐसा नहीं है कि उठाया और मुंह में भर लिया। नहीं नहीं मूंगफली को तो मूंगफली के अंदाज में ही खा सकते हैं। मूंगफली खाने के लिए छिलके को तोड़ना पड़ता है दाने कम छिलके ज्यादा, यदि आपके पास समय नहीं है, धैर्य नहीं है तो फिर आपके बस का मूंगफली खाना नहीं है। मूंगफली अक्सर पढ़ें लिखे समझदार लोग खाते हैं, मूंगफली को छिलके से अलग करना आसान नहीं होता इस काम के लिए बहुत सारा धैर्य चाहिए और आज किसी के पास इतना धैर्य नहीं है कि वह मूंगफली के छिलके को तोड़ें। बहुत सारे लोग तो छिलके सहित ही मूंगफली को खा लेते हैं भले ही मूंगफली खाने में थोड़ी मिट्टी भी क्यों न खाने में आ जाएं। गीली मूंगफली तो तब भी आसान होती है पर जो सुखी हुई मूंगफली होती है उसे छिल पाना हर किसी के बस का नहीं होता। अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि कोई इस बीच आ जाता मूंगफली छिलने तो खाना आसान हो जाता। मूंगफली खाने में तो अच्छा लगता है पर उसका छिलका ही परेशान करता है। मूंगफली के साथ अक्सर दुनियादारी पर विचार करने लगते हैं। यह संसार भी मूंगफली की तरह ही है कि जो अच्छा भला है सब उसके हो जाते हैं और जो छिलके की तरह हैं उससे सभी किनारा करने लगते हैं। कोई भी छिलके का क्या करें छिलका एक समय के बाद बोझ हो जाता है। छिलका है जल्दी फेंकों किसी काम का नहीं है पर जो थोड़ा समझदार होते हैं वे छिलके का भी उपयोग कर लेते हैं छिलके को अलाव में डालकर आग जला लेते हैं, धान की भुंसी जिस तरह काम आती है उसी तरह से मूंगफली के छिलके का भी उपयोग किया जा सकता है। यह आप पर है कि जीवन में चीजों का उपयोग आप कैसे करते हैं और कैसे दुनिया को देखते हैं। छिलके से अक्सर आदमी छुटकारा पाना चाहता है।

मूंगफली तो मूंगफली ही है दाने को खाने के लिए हर कोई मूंगफली को छीलता है, दाने का अलग ही अर्थ और आनंद...समय पास करने के लिए भी मूंगफली को फोड़ते रहते हैं, मूंगफली का स्वाद और खाने का अंदाज भी अलग-अलग ही होता है। हर किसी के अनुभव में मूंगफली अलग से ही एक दुनिया लेकर आती है, जब बस या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा मन मुताबिक मूंगफली ही मिलती है, पांव भर मूंगफली ले लीजिए और रास्ते भर फोड़ते रहिए, समय और संसार पर विचार करते रहिए कि क्या कुछ दाने की तरह है और क्या कुछ छिलके की तरह, दुनिया में कहां किसे कितना महत्व देना है और कहां से दुनिया की राहें अलग हो जाती हैं यह सब मूंगफली के संदर्भ से समझ में आता है। मूंगफली हमारे अनुभव संसार का विस्तार करती है। समय है और समय को निकालना है तो मूंगफली खाने से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता।

मूंगफली खाते समय आपके पास खूब समय होना चाहिए। यदि समय नहीं है तो फिर मूंगफली का आनंद कैसे ले सकते। जिंदगी को आनंद के साथ जीने का अंदाज ही अलग होता है। खाने को तो लोग बादाम भी खाते हैं पर बादाम में वह दुनिया नहीं होती जो मूंगफली के साथ होती है, मूंगफली के साथ मित्रों की भी दुनिया होती है

अंकुरण

सत्येन्द्र पाण्डेय

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

प्रमिला चौहान- बंधुवा मजदूरी से नेतृत्व की नई फसल तक

प्रमिला चौहान का जन्म खंडवा जिले के खालवा तहसील के ग्राम रेहटिया में एक खेतिहर कोरकू आदिवासी मजदूर परिवार में हुआ। हालांकि उनका पालन पोषण मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहने वाली ताप्ती नदी के किनारे बसे सिहावल गांव में हुआ। इसका कारण यह था कि बचपन में प्रमिला की तबियत बहुत खराब रहती थी और उन्हें बार बार सेंधवाल के अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। सेंधवाल में उनकी नानी का घर था। नाना का देहांत हो चुका था और प्रमिला के कोई मामा नहीं थे। लेकिन मुश्किलें तो यहां भी थी हीं। उनकी नानी का खेत साहूकार के पास गिरवी रखा हुआ था जो नाना के पिता के समय से ही गिरवी था। साहूकारी इस इलाके की एक बड़ी समस्या आज तक बनी हुई है। छोटे किसान अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं। उसको चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करके ब्याज चुकाते रहते हैं लेकिन मूलधन मुश्किल से ही चुका पाते हैं क्योंकि ब्याज की दरें बहुत ऊंची और कानून की परिधि से बाहर होती हैं। प्रमिला के पिता भी इस कर्जे को चुकाने के लिए बरसुदिया यानी बंधुवा मजदूरी करने लगे। इधर घर में दूसरा ही संकट था जो उनकी मां झेल रही थीं। घर में एक के बाद एक बेटियां पैदा हो रही थीं और प्रमिला की नानी की जिद थी कि एक बेटा जरूर पैदा हो। दो बेटियां तो जन्म के बाद जीवित भी नहीं बच पाई थीं। एक दिन उनकी मां ने प्रमिला को साथ में लिया और परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने चली गईं।

पिता ने दो साल हरदा जिले के एक गांव में बंधुवा मजदूरी की जिसके एवज में उन्हें साल भर में आठ हजार रुपया और एक बोरा गेहूं हासिल होता था। लेकिन यह साहूकार की कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए फिर पूरा परिवार चल देता है बुरहानपुर की तरफ। मां और पिता दोनों केले के खेतों में जीतोड़ मेहनत करते और पेट काटकर पैसे बचाने की कोशिश करते। प्रमिला अपनी बहनों की देखभाल के लिए झोपडी में रहती और घर का काम भी करती थी। पिता जो काम करते थे उनका इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए होता था और मां की मज़दूरी से घर के खर्चे और खाना आदि संभाला जाता था। एक बार मां की तबियत खराब हो जाने से काम छूट गया और घर में फांकों की नौबत आ गई।

एक दिन बहन भूख के कारण रो रही थी तभी प्रमिला को कुछ पड़ौसी बच्चे कहीं से खाना लाते हुए दिखाई दिए। इनसे पूछा तो पता चला कि गांव में एक जगह पंगत हो रही है और खाने के बाद फेंक दिए गए खाने में से बीनकर लाए हैं। प्रमिला ने भी सोचा कि बहनों को वहीं से बीनकर कुछ खिला देगी लेकिन जब वह ऐसा कर रही थी तभी लोगों ने देख लिया और इनके हिस्से में स्वादिष्ट भोजन की बजाय पिटाई और अपमान ही आया।

प्रमिला के पिता देर रात घर लौटकर आते तो प्रमिला के पास बहुत सवाल होते जैसे कि अमीर कैसे बन सकते हैं? उसे अमीर बनना था ताकि वे सब लोग भरपेट खाना खा सकें। पिता बोलते थे कि पढ़ाई करने से अमीर बन सकते हैं। लेकिन प्रमिला को विश्वास नहीं होता था क्योंकि पढ़ें लिखे तो उसके पिता भी थे परंतु मजदूरी करते थे। बहरहाल कुछ समय बाद पिता मजदूरी करने महाराष्ट्र चले गए। वह समय परिवार के लिए बहुत कष्टकारी था। लेकिन कुछ साल बाद वे लौटकर आए तो साहूकार का कर्जा चुक गया और जमीन वापिस मिल गई। अब वे सब अपने खेत में काम करते और जो अनाज पैदा होता उस पर परिवार का अधिकार था। यह अहसास कितना आह्लादकारी था इसको वही समझ सकता है जिसने बंधुवा मजदूरी से अपनी खुद की फसल तक की यात्रा मुकम्मल की हो। जमीन और घर में अन्न आया तो पढ़ाई की ललक फिर पैदा हुई। दाखिले के लिए गईं तो उनकी प्रतिभा और आयु देखकर चौथी कक्षा में उनका दाखिला हो गया। आठवीं के बाद आगे की पढ़ाई कभी खालवा तो कभी खंडवा। पहले मिशन आश्रम फिर सरकारी हॉस्टल। इन सबके लिए जितना पैसा चाहिए था वह घर में नहीं था पर पिता ने कर्ज लिए, प्रमिला ने खुद कहीं काम किया और दूसरों से मांगकर कपड़े पहने। लेकिन उम्मीद की गली को छोड़ा नहीं। खुद भी पढ़ती रहीं और बहनों को भी पढ़ाया जो आज शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

घर में अन्न आया तो पढ़ाई की ललक फिर पैदा हुई। दाखिले के लिए गईं तो उनकी प्रतिभा और आयु देखकर चौथी कक्षा में उनका दाखिला हो गया। आठवीं के बाद आगे की पढ़ाई कभी खालवा तो कभी खंडवा। पहले मिशन आश्रम फिर सरकारी हॉस्टल। इन सबके लिए जितना पैसा चाहिए था वह घर में नहीं था पर पिता ने कर्ज लिए, प्रमिला ने खुद कहीं काम किया और दूसरों से मांगकर कपड़े पहने। लेकिन उम्मीद की गली को छोड़ा नहीं। खुद भी पढ़ती रहीं और बहनों को भी पढ़ाया जो आज शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

फसल से प्रमिला का लगाव शायद इसी कारण से आज तक कायम है और उन्होंने हुनर की पाठशाला तैयार की तो जमीन का एक टुकड़ा खरीदा भी जिस पर वे खुद खेती करती हैं और अपनी फसल उगाती हैं।

घर में अन्न आया तो पढ़ाई की ललक फिर पैदा हुई। दाखिले के लिए गईं तो उनकी प्रतिभा और आयु देखकर चौथी कक्षा में उनका दाखिला हो गया। आठवीं के बाद आगे की पढ़ाई कभी खालवा तो कभी खंडवा। पहले मिशन आश्रम फिर सरकारी हॉस्टल। इन सबके लिए जितना पैसा चाहिए था वह घर में नहीं था पर पिता ने कर्ज लिए, प्रमिला ने खुद कहीं काम किया और दूसरों से मांगकर कपड़े पहने। लेकिन उम्मीद की गली को छोड़ा नहीं। खुद भी पढ़ती रहीं और बहनों को भी पढ़ाया जो आज शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

बारहवीं में परीक्षा के दौरान वे बीमार हो गईं, बेहद गंभीर पीलिया। शरीर में खून बहुत कम हो गया। जैसे तैसे जान बची लेकिन कुछ पेपर नहीं दे सकीं। स्वस्थ होने के बाद एक सामाजिक संस्था के बारे में पता चला और वे उसके साथ जुड़ गईं। वे कोरकू आदिवासी गांवों में आंगनवाड़ी, मनरेगा और पोषण आदि पर काम करती थीं। इतने अच्छे काम के साथ मासिक आधार पर थोड़ा ही सही लेकिन मानदेय भी मिलता था। यहीं तौसीफ और अन्य कुछ साथियों से मुलाकात हुई। बारहवीं की परीक्षा देने और संस्था में लैंगिक भेदभाव और शोषण को नजरअंदाज किए जाने के मुद्दे पर संस्था से कुछ मतभेद हुए और उन्होंने काम छोड़कर परीक्षा दी, पास हुई और स्नातक में दाखिला ले लिया। अब पढ़ाई भी करती और आजीविका के लिए कभी किसी एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट का काम तो कभी अखबार के ग्राहक बनाने की नौकरी, यही सब करती रहीं। इसी दौर में एक दिन तौसीफ से दोबारा भेंट हुई जो उन दिनों एक गोदाम को तोड़ने के काम में लगा हुआ था। तौसीफ के काम भी सब ऐसे ही थे। कभी मेकेनिक तो कभी सब्जी का ठेला। दोनों ने मिलकर सोचा कि अपनी एक संस्था बनानी चाहिए ताकि हम अपने समुदाय की बेहतरी के लिए खुद की मर्जी से काम कर सकें। इस योजना में तौसीफ की बहन नीलोफर और कुछ अन्य मित्रों को भी जोड़ गया। संस्था का नाम नीलोफर ने सुझाया: मुश्त। यानी बंधी हुई मुट्ठी। एकता का प्रतीक। इस तरह एकता की यह यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंची। जाहिर है, यह काम नौकरी करने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इसी बीच तौसीफ को चेंजलूम की एक फेलोशिप मिल गई और उससे प्राप्त राशि से वे सभी मिलकर काम करने लगे। आमतौर पर प्रमिला और नीलोफर बस से गांव गांव जाते और काम करते। सौ से अधिक युवाओं को आजीविका प्रशिक्षण दिया गया और अनेक युवा रोजगार से जुड़ सके। कुछ समय बाद टायसिया फाइंडेशन से कुछ सहयोग मिलना शुरू हुआ। 2018 में विप्रो से संस्था को सीड फेलोशिप प्राप्त हुई जिससे काम में विस्तार आना शुरू हुआ। प्रमिला भी अपने कर्जे उतार सकी और अपने पिता का इलाज करवाया जो इन दिनों डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और पेरालिसिस का आघात झेल चुके थे।

इस दौर में संस्थाओं से छोटे बड़े सहयोग मिल रहे थे और देश में अनेक दोस्तों से परिचय हो रहा था जो संस्था के कामकाज में सहयोग करते थे लेकिन स्थानीय स्तर पर मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। संस्था के सह संस्थापक के मुस्लिम होने के कारण उन्हें अनेक लोगों द्वारा समाज में अलग तरह से पेश किया जाता था और मुश्किलें खड़ी की जा रही थीं। लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा और कोविड आपदा के समय सैकड़ों परिवारों के लिए राशन, दवाओं और ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराई। इसके लिए उन्हें अनेक संस्थाओं से सहयोग भी हासिल हुआ। हुनर की पाठशाला भी तैयार हुई।

आपदा के बाद संस्था को नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की अंकुरण परियोजना से जुड़ने का अवसर मिला जिसने संस्था के विस्तार में प्रस्थान बिंदु की भूमिका निभाई। न केवल संस्था की संस्थागत क्षमताओं और आर्थिक संसाधनों का विस्तार हुआ बल्कि प्रमिला की नेतृत्व क्षमता में भी गुणात्मक विस्तार हुआ और आज वे अपने जैसी दुसरे युवा साथियों के नेतृत्व को तौयार कर रही हैं।

जब सुरमय गीतों की शाम ढल गई

भोपाल। सुपरिचित तरंग म्यूजिकल ग्रुप द्वारा पोलीटेक्निक सभागृह में 'गीतों का कारवाँ' के आयोजन में राजधानी के सिंगरों ने महान गायकों और गायिकाओं भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के गीतों से कब खुशनुमा सुरमयी शाम को खूबसूरत रात्रि में रूपान्तरित कर दिया, पता ही नहीं चला। इशाक अली इसके आयोजक और सह आयोजक सिंगर एड प्रदीप शर्मा थे। कार्यक्रम के अतिथिगण गायक और लेखक पंकज पाठक, लईक साहब, प्रदीप जी, शंकर मूर्ति और सभी गायकों का शॉल से सम्मान किया गया।वॉइस ऑफ़ रफ़ी परवेज़ ख़ान और इशाक अली के साथ मुकेश की आवाज में मज़हर अली थे। प्रदीप शर्मा, नंदिनी सोमानी, दिव्यांका दुबे, ब्लेसी सोमानी, सैमुअल जॉन, सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी एके श्रीवास्तव, लईक अहमद, श्रीमती तिवारी के गीतों ने ऐसा वातावरण बनाया कि जैसे मौलिक गीतों को साक्षात प्रस्तुत किया जा रहा हो। परवेज़ ने जानेबहार हुस्न तेरा, नंदिनी ने सोलह बरस की बाली उमर को सलाम, ब्लेसी ने बाहों में चले आओ, मज़हर ने वफ़ा जिनसे की बेवफ़ा हो गए की शानदार प्रस्तुति की। नन्हें गायक आदित्य यादव ने भी मोहम्मद रफ़ी का एक तराना बेहद खूबसूरती से पेश किया। प्रदीप ने दिल ऐसा किसी ने तोड़ा, ओ हंसिनी तथा वो शाम कुछ अजीब थी की बेहतरीन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के एंकर राजा यादव ने अपनी अदायगी से प्रभावित किया।

विद्युत मंडी पेंशनरों की मासिक बैठक 10 को

बैतूल। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक 10 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से कैम्पेन हाउस परिसर लिंक रोड बैतूल में आयोजित होगी। जिसमें अंशदायी कैश लैस चिकित्सा योजना की पूर्ण जानकारी के साथ योजना के संबंध में फैलाये जा रहे भ्रम, संशय पर नोडल कंपनी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश की जानकारी दी जाएगी। पेंशनर के साथ महंगाई राहत के संबंध में किए जा रहे भेदभाव, तथा अनावश्यक रूप से राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49(6) के बहाने, केंद्र द्वारा घोषित तिथी व दर से पेंशनर को भुगतान नही करने पर विरोध स्वरूप आगामी रणनीति पर चर्चा एवं इसकी रुप रेखा पर सदस्यो के सुझाव, जिसे केंद्रीय कार्यकारिणी के समक्ष विचार हेतु रखा जा सके पर चर्चा की जायेगी।

जिले के 1 लाख 68 हजार 416 बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक,राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 12 अक्टूबर को

बैतूल। राष्ट्रीय पल्स पोलियों अभियान का अतिरिक्ति चरण 12 अक्टूबर रविवार को प्रदेश के चयनित 18 जिलों जिनमें बैतूल भी शामिल है आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकामें डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे ने बताया कि रविवार को प्रथम दिवस बूथ पर एवं दूसरे एवं तीसरे दिन 13 और 14 अक्टूबर को घर-घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के अनुमानित कुल 1 लाख 68 हजार 416 बच्चों को पोलियों की खुराक दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 226 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1683 कुल 1909 टीकाकरण बूथ बनाये गये हैं। बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, जिले के क्रासिंग पाईंटों में 88 बूथ बनाकर दवा पिलाई जाएगी। साथ ही जिले में हाई रिस्कर एरिया, ईंट भट्टे, निर्माण स्थल, मेले, झुग्गी-झोपड़ी, घुमक्कूड़ आबादी स्थल को भी चिन्हित कर 21 मोबाइल टीमों के द्वारा पोलियो की दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। दवा पिलाने के लिए 4036 टीकाकर्मी एवं सुपरवीजन के लिए 357 सुपरवाईजरों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पल्स पोलियो की दवा पीने से कोई भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे वंचित न रहे।

कांक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की तकनीकी समिति की बैठक आयोजित

बैतूल। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कांक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की तकनीकी समिति बैठक का आयोजन 8 अक्टूबर को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बैतूल में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि बैठक में एमडी डॉ रोहित परते, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉ ऋषि माहोर द्वारा बच्चों का परीक्षण कर सर्जरी के लिये भावेश पिता राजेश प्रजापति 5 वर्ष निवासी आठनेर, अनमोल पिता संदीप उइके 3 वर्ष 7 माह निवासी सोनाली बंडाला आमला, कुमारी याचना पिता अनिल सूर्यवंशी 3 वर्ष 4 माह निवासी रगडगांव प्रभात पट्टन को चिन्हित किया गया। चिन्हित बच्चों को इंदौर के अरविन्दों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेस हॉस्पिटल भेजा जाएगा। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश परिहार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ विनोद शाक्य एवं आरबीएसके मैनेजर योगेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

नपा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में आज 9 अक्टूबर को जल सप्लाई रहेगी बाधित

बैतूल। गंज स्थित अंडरब्रिज पर रेलवे द्वारा सड़क निर्माण कार्य के दौरान बुधवार दोपहर नगर पालिका की मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते गुरुवार 9 अक्टूबर को निर्धारित क्षेत्रों में जल सप्लाई बाधित रहेगी। जल प्रदाय शाखा के प्रभारी धीरेन्द्र राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंडरब्रिज क्षेत्र में सडक़ का निर्माण कार्य चल रहा था, इसी दौरान जेसीबी से खुदाई के समय मुख्य पाइपलाइन टूट गई।

विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की पीड़िता परिवारों से मुलाकात

परासिया में इलाज के बाद और एक बच्चा गंभीर, नागपुर में वेंटिलेटर पर भर्ती

बैतूल। कोल्ड्रिफ सिरप से आमला ब्लाक के दो बच्चों की मौत की आशंकाओं के बाद अब एक और बच्चे को गंभीर हालत में नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और बच्चा वेंटिलेटर पर है। परिजन इलाज में कोल्ड्रिफ सिरप दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बैतूल सीएमएचओ डॉ मनोज हुरमाडे ने जांच हेतु चार डॉक्टरों की समिति गठित की है। गंभीर रूप से बीमार बच्चे की पहचान, आमला विकासखंड के ग्राम टीकाबर्री निवासी हर्ष पिता राकेश के रूप में हुई है। बच्चे के फूंफा निलेश ने बताया कि 4 अक्टूबर को नागपुर के अजनी स्थित मेडिकल कॉलेज में बच्चे को भर्ती कराया गया था। उसकी हालत पहले दिन जैसी ही बनी हुई है और डॉक्टरों ने कोई सकारात्मक उम्मीद नहीं जताई है। निलेश के अनुसार, 26 सितंबर को परासिया के डॉक्टर को हर्ष को दिखाया गया था। वहां पर्ची पर लिखी गई दवाएं दी गईं। लेकिन 1 अक्टूबर तक बच्चे की हालत

बिगड़ गई। 4 अक्टूबर को नागपुर लाया गया, जहां बच्चे का क्रिएटिनिन लेवल 250 (mg) पाया गया। निलेश ने इलाज से जुड़ा पर्चा और कथित तौर पर दी गई कोल्ड्रिफ सिरप की शीशी का फोटो भी साझा किया है। इस बीच, हरन्या पंचायत

पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा, उठाई एक करोड़ मुआवजे की मांग

बैतूल। जिले के जामुन बिछुआ और कलमेश्वरा गांव में जहरीले सिरप से हुई मासूमों की मौत के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। श्री डागा ने इस हृदय विदारक घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैतूल जिले के आदिवासी बहुल इलाकों में न डॉक्टर हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ और ना ही जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने जिस जहरीले कफ सिरप को बिना जाँच किए अनुमति दी, वही मौत की वजह बन गया। कांग्रेस ने मृतकों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने, दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और पूरे मेडिकल सप्लाई चेन की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही श्री डागा ने कहा कि अगर सरकार ने आँखें नहीं खोलीं, तो कांग्रेस सडक़ों पर उतरकर आदिवासी क्षेत्रों की जानलेवा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।

निवासी आदिवासी युवक मोहित धुर्वे के डेढ़ महीने के बेटे भानु की भी मौत 30 सितंबर को हो गई। बच्चे को सर्दी-खांसी की शिकायत पर 29 सितंबर को परासिया ले जाया गया था। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया था।

मेडिकल स्टोर्स की जांच के निर्देश, 2 स्टोर सील

बैतूल में संदिग्ध कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत के मामलों के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर जिले की दवा दुकानों और एजेंसियों की जांच की गई। इस दौरान दो मेडिकल स्टोर सील किए गए, जबकि यह सामने आया कि कोल्ड्रिफ सिरप पिछले 13 साल से जिले में नहीं बिका। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज हुरमाडे ने दवा दुकानों की सूची प्रशासन को सौंपी थी। इसके बाद सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए गए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीएमओ के नेतृत्व में जिलेभर में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। एसडीएम अभिजीत सिंह के नेतृत्व में बैतूल में मेडिकल एजेंसियों और दुकानों की गहन जांच हुई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि कोल्ड्रिफ सिरप की जिले में न तो कोई एजेंसी है और न ही पिछले 13 वर्षों से इसकी बिक्री हुई है। आमला ब्लॉक के बोरदेही क्षेत्र में बीएमओ डॉ. अशोक नरवरे की टीम ने जांच के दौरान दो मेडिकल स्टोर सील किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सिरप पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमें अभी भी जांच में जुटी हुई हैं।

इनका कहना है –

मृतक भानु के पिता मोहित के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि टीकाबर्री गांव के हर्ष के नागपुर में भर्ती होने की विस्तृत रिपोर्ट भी मंगवाई जा रही है। इस मामले में जांच के लिए गठित चार डॉक्टरों की समिति अब तक बैतूल में मृत दोनों बच्चों के परिजनों के बयान दर्ज कर चुकी है। अभी हमीदिया और एम्स भोपाल से रिपोर्ट आना बाकी है।

– डॉ. मनोज हुरमाड़े, सीएमएचओ, बैतूल

विधायक डॉ. पंडाग्रे ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

बैतूल। आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की टीम और कार्यकर्ताओं के साथ आमला क्षेत्र के कलमेश्वरा एवं जामुनबिछुआ ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने शोक-संतप्त परिवारों से भेंट की, उन्हें सांत्वना दी और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दल भेजने के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने का कहा कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनर्रावृत्ति न हो। शोकाकुल परिवारों से भेंट के बाद डॉ. पंडाग्रे और श्री पवार ने आसपास के ग्रामों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से संवाद भी किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि संदिग्ध या अमानक कफ सिरप बच्चों को न दें। साथ ही प्रशासन को निर्देशित किया कि क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया जाए और किसी भी बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर तुरंत रिपोर्टिंग और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

भावांतर योजना का लाभ लेने वाहन रैली का आयोजन

बैतूल। मध्यप्रदेश शासन की भावांतर योजना सोयाबीन के जिले में प्रचार प्रसार के लिए मोटर साईकल, फोर व्हीलर, वाहन रैली निकाली गई। यह रैली शिवाजी ओपन आडोटोरियम बैतूल से प्रातः 10 बजे जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पंवार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। वाहन रैली शिवाजी ओपन आडोटोरियम बैतूल से कोठी बाजार, मुख्य बस स्टेण्ड, थाना चौक रोड, गणेश चौक से होते हुए कॉलेज चौक, बाबू चौक, मस्जिद चौक, रेल्व स्टेशन रोड, मैकेनिक चौक, बडोरा चौक, कृषि उपज मंडी बडोरा पहुंची। तत्पश्चात गेंदा चौक, कारगील चौक, डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक, पेट्रोल पंप चौक, कोठी बाजार, मुख्य बस स्टेचड होते हुये कार्यालय उप संचालक किसान कल्यापण तथा कृषि विकास विभाग बैतूल में समापन किया गया। वाहन रैली के पूर्व अतिथियों का स्वागत डॉ. आनंद कुमार बडोनिया उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला बैतूल के द्वारा किया गया। भावांतर योजना अंतर्गत किसानों को सोयाबीन उपज का उचित मूल्यप प्रदान करने के लिए भावांतर योजना सोयाबीन खरीफ वर्ष 2025 राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। किसान के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि को भावांतर योजना सोयाबीन वर्ष 2025 अंतर्गत किसान के बैंक खाते में जमा किया जावेगा। योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए कृषक का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन अवधि 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक है। 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषक द्वारा अपनी उपज का विक्रय अधिसूचित कृषि उपज मंडीयो में किया जावेगा। किसान से अपील की है कि अंतिम तिथि 17 अक्टुबर के पूर्व सोयाबीन पंजीयन के लिए सहकारी समितियों में जाकर अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर भावांतर योजना का लाभ लेवे।

धम्म दीक्षा दिवस एवं वर्षावास दिवस 12 को

बैतूल। पंचशील बुद्ध विहार समिति और बुद्धिस्ट सोसायटी आफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में पंचशील बौद्ध विहार सदर में धम्म दीक्षा दिवस एवं वर्षावास को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि धम्म दीक्षा दिवस एवं वर्षावास समापन कार्यक्रम 12 अक्टूबर को पंचशील बुद्ध विहार में पूज्य भंते दीपांकर जी के सानिध्य में सम्पन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम जिसमें जिले से बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक-उपासिकाएं सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 1 बजे पंचशील धम्म ध्वज फहराने के साथ किया जाएगा। इसके पश्चात रैली, बुद्ध वंदना, परित्राण,भगवान बुद्ध के उपदेशों का वाचन, धम्म दीक्षा और पूज्य भंते जी द्वारा बौद्ध उपासक एवं उपासिकाओं को धम्म देशना दी जाएगी। जिसमें धम्म के मूल सिद्धांतों एवं सम्यक जीवन शैली पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। कार्यक्रम के अंत में पूज्य भंते जी को धम्मदान दिया जाएगा। समिति ने सभी से कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

सक्षम कार्यक्रम हेतु प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों का एकदिवसीय उन्मुखीकरण एवं समीक्षा बैठक संपन्न

बैतूल/भौंरा। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल विवेक पांडे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड शाहपुर में प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए एकदिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 71 प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए। सहायक आयुक्त विवेक कुमार पांडे ने ऑनलाइन जुड़कर सभी विद्यालय प्रमुखों से संवाद किया तथा सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही सक्षम कार्यक्रम के सत्रों कों प्रत्येक शाला की समय सारणी से जोड़ कर गुणवत्तापूर्ण संचालन किया जाए और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जीआर बर्डे ने शिक्षण कार्यों एवं स्टाफ दायित्वों में समानता लाने की दिशा में अपने विचार साझा किए और निर्देश दिया कि संकुल प्राचार्य मासिक बैठक में सक्षम एजेंडा की समीक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल करें। संदीपनि बालक शाला शाहपुर के प्राचार्य कमलेश शर्मा सर द्वारा विद्यालय में संचालित सक्षम कार्यक्रम कों लेकर अपने अनुभव साझा किया गए साथ मास्टर ट्रेनर गणेश कुमरे द्वारा डेमो सत्र आयोजित किया गया। जिनमें वास्तविक शिक्षण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टिकोण पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा शिक्षण में इसे एकीकृत करने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की गई।जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री निष्ठा सौदावत ने सक्षम कार्यक्रम के पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं अनुभवों का विश्लेषण प्रस्तुत किया और जिला स्तर पर चल रही गतिविधियों की झलक साझा की। ब्लॉक प्रबंधक मीना सातनकर ने सक्षम कार्यक्रम के विभिन्न कंपोनेंट्स पर चर्चा करते हुए सेशन रिपोर्टिंग, एलएमएस प्रणाली, मैजिक मित्र चैटबॉट एवं लाइव एसक्यूएमएफ का डेमो सेशन दिया और जीवन कौशल सत्र क्रमांक 7 का आयोजन सत्र संरचना और बारीकीयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में शाहपुर विकासखंड के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को सक्षम कार्यक्रम के सफल संचालन और विद्यालय में सत्रों की प्रभावी निगरानी हेतु सशक्त किया।

जिले के मतदाता 17 अक्टूबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए कर सकेंगे दावे-आपत्ति

स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

बैतूल। जिले के मतदाता 17 अक्टूबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए दावे आपत्ति कर सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को स्टेंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे सहित जनपद अध्यक्ष, सदस्य, पाषर्द, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमद उपस्थित रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद ने बताया कि तीन चरणों में मतदाता सूची पुनरीक्षण किया जा रहा है। तृतीय चरण के तहत 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 3 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से दावे आपत्ति केंद्र पर दावे आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय निकाय के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वार्ड में तथा पंचायतों में दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किए गए है। उन्होंने बताया कि चेकलिस्ट की जांच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस किया जाएगा। दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तथा निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस में प्रविष्टी की अंतिम तिथि 1 नवंबर निर्धारित है। वहीं 4 नवंबर तक दावे आपत्ति की चेकलिस्ट तैयार करना। 7 नवंबर तक चेकलिस्ट की जांच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस करना और फोटोयुक्त और फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट किया जायेगा। इसके बाद 10 नवंबर को फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को बेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध 12 नवंबर को किया जाएगा। फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड, ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 13 नवंबर को होगा।

आयुष विंग के नि:शुल्क जांच शिविर में 157 मरीज हुए लाभान्वित

झंडू लिमिटेड के सौजन्य से हुआ नि:शुल्क बीएमडी जांच शिविर

बैतूल। आयुष विंग जिला चिकित्सालय बैतूल में 8 अक्टूबर को हड्डियों की सेहत को लेकर नि:शुल्क बोन मैरो डेंसिटी (बीएमडी) टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला, जिसमें कुल 157 लोगों ने अपनी हड्डियों की जांच करवाई। इस जांच के माध्यम से हड्डियों के घनत्व का पता लगाया गया।

आयुष विंग प्रभारी डॉक्टर प्रियंका उईके, विशेषज्ञ आयुर्वेद ने बताया कि बीएमडी टेस्ट ड्यूल एक्स-रे एब्जॉर्प्शनोमेट्री तकनीक पर आधारित है, जो हड्डियों की मजबूती का सटीक और विश्वसनीय आकलन करती है। डॉ. प्रियंका उईके ने कहा कि आजकल बढ़ती उम्र, असंतुलित भोजन और शारीरिक निष्क्रियता के कारण लोगों में हड्डियों की दुर्बलता तेजी से बढ़ रही है।

कढ़ाई गौशाला में गौवंश की मौत के मामले में राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने सौंपा ज्ञापन

एसडीएम, सीएमओ और पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश

बैतूल। नगर पालिका द्वारा कढ़ाई में संचालित गौशाला में बीते दो माह से लगातार गौवंश की मौतें हो रही हैं। राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने इसे हिन्दू आस्था से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय हिन्दू सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय, गौ सेवक गोलू सोनी, दीपक कोसे, राहुल खवादे, सत्यम विश्वकर्मा, मोहित वर्मा, अजय खवादे सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने बताया कि पिछले दो महीनों में गौशाला में लगभग एक दर्जन गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी सामने आया है कि कुछ मृत गौवंश को कुत्ते लोंच कर खा रहे हैं। यह दृश्य विचलित करने वाला है, हिन्दू समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गौशाला में पशु आहार की कमी है। यही कारण है कि गौवंश भूख और बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। प्रशासनिक अनदेखी के चलते इनकी मृत्यु के पश्चात न तो किसी प्रकार का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और न ही उन्हें विधिवत दफनाया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। अपर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम, नगरपालिका सीएमओ और पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर पहुँचकर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने यह भी मांग की है कि हर एक मृत गौवंश का पोस्टमार्टम कर उसकी वास्तविक मृत्यु का कारण पता लगाया जाए और अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाह पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्यवाही की जाए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने कहा कि गौवंश की रक्षा करना हर हिन्दू की जिम्मेदारी है और प्रशासन को भी यह समझना चाहिए कि यह हिन्दू आस्था से जुड़ा मामला है। गौमाता को भूख-प्यास और बीमारी से मरने देना अत्यंत निंदनीय है। राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदेश संयोजक पवन मालवीय ने कहा कि गौशाला में लगातार हो रही गौवंश की मौतें बेहद दुखद और प्रशासन की घोर लापरवाही का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दू समाज की आस्था का प्रतीक गौमाता अगर भूख, बीमारी और कुत्तों के हमले से मर रही है, तो यह शासन-प्रशासन के लिए शर्म की बात है। उन्होंने मांग की कि दोषी अधिकारियों की तत्काल जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

गांव-गांव चल रहा दूध समृद्धि संपर्क अभियान

बैतूल। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरूआत 3 अक्टूबर से की गई है, जो आज 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 10 या 10 से अधिक गौ-भैंस वंशीय पशु रखने वाले पशुपालको के घर-घर जाकर भेंट की जा रही है और पशु पालकों से पशुओं के रखरखाव, खानपान आदि के संबंध में चर्चा कर रहे है। पशुपालकों के पास उपलब्ध पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त कर दुग्ध व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय बनाने के विषय में चर्चा की गई। अभियान के दौरान पशुपालकों को उन्नत नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु पोषण के लिए संतुलित पशु आहार का महत्व एवं इससे होने वाले लाभ जैसे अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन, बांझपन से मुक्ति आदि विषय में जानकारी दी। पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या-क्या सावधानियां रखी जाना चाहिए और कौन-कौन से टीकाकरण कराए जाना चाहिए के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के पर्यवेक्षक के लिए संयुक्त संचालक पशु पालन एवं डेयरी भोपाल संभाग भोपाल डॉ. सुनील परनाम एवं राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी डॉ. एलिजाबेथ थॉमस ने जिले ने विभिन्न ग्रामों में पशुपालकों से चर्चा की।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

क्या सत्तापक्ष द्वारा प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग संभव है ?

समय-समय पर प्रतिपक्ष द्वारा सत्तापक्ष पर प्रशासन तंत्र के राजनीतिक उपयोग को लेकर आरोप लगाए जाते रहे हैं। चूंकि आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला राजनीति में 'सक्रिय राजनीति' का पर्याय हुआ करता है, इसलिए इसे गंभीरता से भी नहीं लिया जाता। वैसे यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि जिनके राजनीतिक हित प्रभावित होते हैं, वे दोषारोपण के माध्यम से अपना हित संवर्धन कर लिया करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसे आरोपों को लिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक तीन से चार दशकों तक दल विशेष की सत्ता अवश्यंभावी थी। लिहाजा उस दौर में सत्तापक्ष के प्रति प्रशासन तंत्र का स्पष्ट झुकाव बहुत हद तक स्वाभाविक माना जा सकता था। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह संभव नहीं।

सत्तासीन दल द्वारा घोषित घोषणापत्र के अनुरूप क्रियान्वयन में स्वाभाविक रूप से प्रशासन तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सत्ता का उलटफेर हो जाने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीते आम चुनाव के परिणाम इसकी गवाही देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन तंत्र या उसके किसी अंग का किसी एक ही दल पर आसक्त होना, संभव नजर नहीं आता। प्रशासन के कर्तव्यपालन में विधिसम्मत प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। जिनका पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। और तो और आम नागरिकों की तर्कशक्ति में भी आशातीत वृद्धि हो चुकी है। लिहाजा यह इतना आसान नहीं रह गया है किप्रशासन तंत्र में रहकर एकतरफा कार्रवाई को मूर्तरूप दिया जा सके।

जहां तक व्यक्तिगत विचारधारा का प्रश्न है, उसे प्रशासन तंत्र के कर्तव्यपालन में बाधक नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि यह विषय तंत्र के अंग के जीवन का आधार है। आंशिक रूप से यह माना जा सकता है कि प्रशासन तंत्र किसी राजनीतिक या आर्थिक दबाव या प्रभाव के चलते कर्तव्यपालन से विमुख हो जाए। लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता के चलते पूर्वाग्रह से युक्त प्रशासन की कार्रवाई को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। यह माना कि तर्कसम्मत का विधिसम्मत होना जरूरी नहीं और विधिसम्मत का तर्कसम्मत होना भी जरूरी नहीं। लेकिन व्यवहार में व्यावहारिकता के महत्व को अंगीकार करना हम भारतीयों के लिए अपने चरित्र का एक अभिन्न अंग है।

निश्चित ही प्रशासन तंत्र के लिए किसी भी मामले में एकतरफा कार्रवाई अब इतनी आसान भी नहीं रह गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने में तुलनात्मक रूप से आम नागरिकों की अपेक्षा राजनीतिज्ञ ही अग्रणी रहे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रतिपक्ष द्वारा सत्तापक्ष की आलोचना को उसका मूलभूत अधिकार माना जाता है। सत्ता की आलोचना प्रतिपक्ष के अस्तित्व को निर्धारित करती है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर निशाना साध कर चला करते हैं। और यह भी सहज स्वाभाविक ही है। किंतु पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आरोप लगाने के लिए आरोप लगा देना, स्वस्थ राजनीति का परिचायक कैसे माना जा सकता है ? वह भी ऐसी स्थिति में जबकि न्यायपालिका के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं।

वैसे भी जैसे-जैसे नागरिकों में राजनीतिक चेतना व्याप्त होती चली जा रही है, वैसे-वैसे दल विशेष के लिए सत्ता उस दल का स्थायी भाव नहीं रह गई है। जब राजनीतिक दृष्टि से उथल-पुथल का दौर हो तब कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर साधिकार समुचित कार्रवाई के लिए सत्तासीन स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यह कार्रवाई बिजली के अनुरूप होना चाहिए तथा पूर्वाग्रह की भावना लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। अनेक अवसरों पर प्रशासन तंत्र को न्यायपालिका द्वारा आड़े हाथों लिया गया है और विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। इतना जरूर है कि प्रशासन तंत्र को स्वच्छंद भी नहीं छोड़ा जा सकता।

हालांकि पूर्वाग्रह से युक्त राजनीतिक विचारधारा के चलते प्रशासन तंत्र के अधिकारों का दुरुपयोग करने का अंदेशा भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज नहीं तो कल दुराग्रह से भरी भावनाओं का दुष्परिणाम भी संबंधित पक्ष को भुगतना पड़ा है। देश प्रदेश का क्षेत्र विशेष, किसी दल विशेष के वर्चस्व वाला हो सकता है। प्रशासन तंत्र किसी क्षेत्र विशेष के प्रति आसक्त और किसी अन्य क्षेत्र विशेष के प्रति विरक्ति भाव अपनाकर भेदभाव न कर सके, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों के क्षेत्र में प्रशासन तंत्र संसाधनों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराता है। जबकि अन्यत्र ऐसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में आम नागरिक तथा उनके प्रतिनिधियों का कुंठित हो जाना भी सहज स्वाभाविक प्रतीत होता है।

यही नहीं अपितु समानता के सिद्धांत पर आधारित विकास प्रक्रिया के अवरुद्ध होने से नागरिकों में असंतोष भी पनपने लगता है। कालांतर में यह स्थिति अराजकता की ओर धकेल दिया करती है।अतः ऐसी स्थिति से बचने के कारगर प्रयास जरूरी है। कुल मिलाकर विशेष रूप से जब राजनीतिक उठापटक का दौर चरम पर हो तब प्रशासन से निष्पक्ष तथा तटस्थ भाव से कर्तव्यपालन की अपेक्षा की जाती है। बेहतर हो यदि प्रशासन तंत्र अपने-अपने कार्यकाल में विधि के अनुरूप कार्रवाई को मूर्त रूप देवे। प्रशासन तंत्र पर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव का असर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर ही सुशासन की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुरूप सत्ता परिवर्तन होने पर भी प्रशासन तंत्र को भयाक्रांत होने से बचाया जा सकेगा। विभागीय अनुशासन का पालन करते हुए कर्तव्यनिष्ठ भावना को अपने चरित्र में शुमार करने पर प्रशासन तंत्र के नुमाइंदों को लोकप्रियता के चरम पर पहुंचते हुए भी देखा गया है। दूसरी ओर विभागीय कार्यवाई से दंडित होते हप्रशासन तंत्र के नुमाइंदों को प्रताड़ना के दौर से गुजरते हुए भी देखा गया है। ऐसे में यह समय की मांग है कि संतुलन के आधार पर प्रशासन तंत्र अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। अन्यथा राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के चलते दो पाटों के बीच पीसने से अधिक कुछ हासिल नहीं हो सकेगा।

संक्षिप्त समाचार

पैदल जा रहे युवक को वाहन ने टक्कर मारी, मौके पर ही हुई मौत

रायसेन, निप्र। रायसेन जिले के बेगमगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा चकला नाले के पास हुआ। एक अज्ञात वाहन ने सड़क पर पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वृंदावन कॉलोनी निवासी अंकित साहू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अंकित साहू अमरचंद साहू के पुत्र थे। अंकित के पिता अमरचंद साहू ने बताया कि उनका बेटा ग्राम सिंहपुर गया था और लौटते समय सड़क किनारे यह हादसा हुआ। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी पर रासुका लगाने सौंपा ज्ञापन

सलामतपुर , निप्र। विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल ने सलामतपुर थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी को एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सिरोंज निवासी असद खान पर रासुका एवं जिला बदर करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगा। थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी को ज्ञापन देते समय देवेन्द्र शर्मा, गोपाल राठौर, अनूप अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

सीहोर जिला पंचायत सीईओ सर्जना यादव ने पदभार संभाला

सीहोर, निप्र। सीहोर जिला पंचायत सीईओ के रूप में सर्जना यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की साल 2020 बैच की अधिकारी हैं। यहां से पहले वह जबलपुर में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने कलेक्टर बालागुरू के. से भेंट की। पदभार संभालने के बाद, सर्जना यादव ने जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और जिले में चल रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

जाम से लोगों को कब राहत मिलेगी ?

सीहोर, निप्र। शहर से निकले पुराने भोपाल-इंदौर हाइवे किनारे स्थित अस्पताल, निजी क्लीनिकों, बैंक और शोरूम के पास पार्किंग की सुविधा नहीं होने से नदी चौराह से लेकर जनसंपर्क कार्यालय के दोनों तरफ दो और चार पहिया वाहन अवैध रूप से पार्क कर दिए जाते हैं, जिससे हाइवे से निकलने वाली बस सहित अन्य बड़े वाहनों को निकलने जगह नहीं बचती है। यही कारण है कि दिन भर में कई बार जाम के हालात बनते हैं। यह समस्या हर दिन की है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। आखिरकार रोज के जाम से लोगों को कब राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय भजन गायन में अंशुल को मिला अवॉर्ड

सीहोर, निप्र। राष्ट्रीय भजन गायन के दौरान शहर के गायक अंशुल जैन ने देशभर से पहुंचे गायक युवाओं को प्रतियोगिता में पीछे छोड़ थर्ड अवॉर्ड प्राप्त किया। क्रांतिकारी राष्ट्रसंत मुनि पुलक सागर महाराज के सानिध्य में उदयपुर में देशभर के युवा गायकों को आमंत्रित कर पुलक आइडियल श्री का आयोजन किया गया। जिसमें अंकुश ने गायन में तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुलक आइडियल श्री में 41 गायक शामिल हुए थे।

छात्रा से छेड़छाड़, परिजन ने दर्ज कराई शिकायत

मंडीबामोरा, निप्र। एक गांव में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 10वीं की छात्रा के पिता ने शिकायत में कहा हैकि आरोपी लंबे समय से उनकी बेटी को तंग कर रहा था। 2 सितंबर को उसके साथ छेड़छाड़ की। जब शिकायत की तो आरोपी के परिजन घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और अपमानित करने लगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है, लेकिन मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

शिक्षा विभाग अंतर्गत संभाग स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता सम्पन्न

हरदा (निप्र)। शिक्षा विभाग अंतर्गत संभाग स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता सोमवार को स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 14 व 19 वर्ष बालक एवं बालिका वर्ग में हरदा, नर्मदापुरम एवं बैतूल जिले के बालक एवं बालिका वर्ग की टीमों ने भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एस. रघुवंशी ने बताया कि सभी वर्ग में लीग मैच खेले जा रहे है। लीग मैच के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर राज्य स्तर हेतु टीम बनेगी। उन्होने बताया कि चयनित खिलाड़ी 19 वर्ष आयु वर्ग के जबलपुर में एवं 14 वर्ष आयु वर्ग के चयनित खिलाड़ी पन्ना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी श्री रघुवंशी ने बताया कि प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, हरदा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक श्री शशांक, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा, जिला ओलम्पिक संघ अध्यक्ष श्री संदीप पटेल ने खिलाड़ियों से परिचय किया। प्रतियोगिता में पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल ने खिलाड़ियों को ''खेलेगा हरदा जीतेगा हरदा'' का उदघोष कर विजय होने की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर श्री जैन ने बच्चों को कहा कि खेल अनुशासन संयम और नियम सिखाता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता शारीरिक बल के अनुरूप खेल का चयन करके खेलना चाहिए। प्रतियोगिता में प्राचार्य श्री संतोष यादव, व्यायाम शिक्षक श्री राजेश बिलिया, ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान, सुश्री मोनिका मेहता, श्री भूपेंद्र सिंह तोमर, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री नीरेंद्र सेवारिक, श्री आशीष सेवारिक, श्री प्रवीण बॉथम, श्री दर्शन खोरे, सुश्री दीक्षा श्रीवास, श्री करण सोनी, श्री राहुल कैथवास, श्री मोहित अवस्थी, श्री अख्तर अहमद, श्री अंकित भूखंडों, श्री हरिभाऊ, सुश्री पुष्पा धोते सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी व खिलाड़ी उपस्थित थे।

पिपरिया में शीघ्र ही एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा : मंत्री श्री विश्वास सारंग

नर्मदापुरम (निप्र)। सोमवार को मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग ने पिपरिया में सांसद खेल महोत्सव आयोजन का मशाल जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री श्री सारंग ने खेल गतिविधि में भाग लेते हुए गोला भी फेंका। खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष श्री पीयूष शर्मा, श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्री हरिशंकर जायसवाल, श्री माधवदास अग्रवाल, श्री संपत मुंदड़ा, श्री संतोष पारे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मंच पर उपस्थित रहे। साथ ही अपर कलेक्टर श्री राजीव रंजन पांडे, एसडीएम पिपरिया श्री देवेंद्र प्रताप, तहसीलदार श्री वैभव बैरागी,

जिला खेल अधिकारी उमा पटेल सहित अन्य अधिकारी गण आयोजन के दौरान उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान ख्याति प्राप्त भजन गायक श्री सुधीर व्यास ने अपने सुप्रसिद्ध भजन यह चमक यह दमक की अद्भुत प्रस्तुति देकर मंत्री श्री सारंग, समस्त जनप्रतिनिधीकरण, अधिकारियों एवम सभी खिलाड़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान सहकारिता तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मंच पर उपस्थित भजन गायक श्री सुधीर व्यास का सम्मान करते हुए उनकी प्रशंसा की एवं कहा कि आपके द्वारा गए भजन से पूरी सभा में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग ने अपने उद्बोधन के दौरान सभा में उपस्थित सभी युवा विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश और दुनिया को आगे बढ़ाना है तो उसका दारोमदार देश के युवाओं के कंधों पर ही है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है कि देश का युवा नवनिर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। देश को युवाओं को खेल से जुड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खेल वह माध्यम है जिससे जो किसी भी व्यक्ति संस्कारित और संयमित कर सकता है। मंत्री श्री सारंग ने अपने उद्बोधन के दौरान स्वामी विवेकानंद से संबंधित एक किस्से को सुनाते हुए कहा कि जब एक युवाओं का दल उनके पास पहुंच कर उनसे उनके ही जैसे संन्यासी जीवन जी कर समाज और स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव के लिए मार्गदर्शन मांगते है तो वे उन्हें खेल से जुड़ने की ही सलाह देते है।

भावांतर योजना में सोयाबीन उत्पादक किसानों का 17 अक्टूबर के पहले कराएं पंजीयन: कलेक्टर विश्वकर्मा

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन और विभागीय योजनाओं की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, शासकीय पत्रों और विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में अभी तक हुए किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर के पहले सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कराएं। सभी एसडीएम को भी किसान पंजीयन कार्य की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार और अधिकारीवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों तथा निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाईन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इनके निराकरण में लापरवाही ना बरती जाए। सीएम हेल्पलाईन प्राप्त होते ही संतुष्टिपूर्ण निराकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने समीक्षा के दौरान कहा कि 50 दिवस से अधिक समयावधि की शिकायतों में कमी नहीं आई है, अधिकारी गंभीरता के साथ लंबित शिकायतों को निराकृत कराएं। उन्होंने विभागवार समीक्षा के दौरान पीओ डूडा को निर्देश दिए कि नगरीय निकायों की शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा निराकरण में तेजी लाएं। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान अधिक संख्या में शिकायतें लंबित होने पर सिविल सर्जन और संबंधित अधिकारियों निराकरण में गति लाने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निराकरण की गति संतोषजनक नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि लगातार निर्देशों के उपरांत भी शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं आई है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों का काम भी निराशाजनक है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को हिदायत देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाईन को गंभीरता से लें और प्राथमिकता से अंतिम निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने टीएल बैठक से अनुपस्थित रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के सहायक संचालक श्री सुमित रघुवंशी को सीएम हेल्पलाईन के निराकरण में उदासीनता बरतने तथा रूचि नहीं लेने पर मोबाईल पर फटकार लगाई। साथ ही कार्यशैली में सुधार लाते हुए गंभीरता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निम्न गुणवत्ता से बंद सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का पुनः अवलोकन करने के निर्देश दिए। साथ ही नॉन अटेन्डेन्ट शिकायतों की भी जानकारी लेते हुए ऊर्जा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, एमपीएसएसी तथा संस्थागत वित्त के अधिकारियों को निर्देशित किया भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति ना हो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सहायक कलेक्टर श्री कुलदीप पटेल, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अनुभागों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे

पीएम किसान सम्मान निधि के 92 प्रतिशत से अधिक किसानों ने ई-केवाईसी कराया

विदिशा , निप्र।भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के पात्र 2 लाख 65 हजार 451 कृषकों में से 2 लाख 46 हजार 407 किसानों के द्वारा ई केवायसी का कार्य पूरा कराया जा चुका है। अर्थात् जिले के 92.83 प्रतिशत किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्ति के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता को पूर्ण करा लिया गया है।शेष किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता से भी अवगत कराते हुए ई-केवाईसी नियत प्रक्रिया अनुसार शीघ्र संपादित कराने से अवगत कराते हुए डोर टू डोर संपर्क कर इस कार्य को मुर्तरुप दिया जा रहा है।

पहल का असर : कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले के पंजीकृत किसानों की एक केवाईसी करने के लिए विशेष पहल की गई थी उन्होंने पटवारी वह कृषि विभाग उद्यान की विभाग के संयुक्त दल को डोर टू डोर संपर्क करने विशेष सिविल आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे इस कारण से जिले में ई केवाईसी के कार्यों में युद्ध गति से संपादन हुआ है। गौरतलाप हो की पीएम किसान सम्मन निधि के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना में पंजीकृत प्रत्येक पात्र कृषक को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। जिले के सभी किसानों को योजना से लाभान्वित कराएं जाने के लिए ई केवाईसी की अनिवार्यता संबंधी कार्य पूरे किए गए हैं। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना तथा खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहारा उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपना आधार सीडिंग, बैंक खाता विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज अपडेट कर योजना का लाभ सतत रूप से प्राप्त करें। कृषकगण पीएम किसान पोर्टल अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी पात्रता एवं भुगतान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कोई भी सोयाबीन उत्पादक किसान भावान्तर योजना से वंचित न रहे: प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर

भावांतर योजना में अभी तक जिले के 5434 किसानों ने कराया पंजीयन

सीहोर (निप्र)। सरकार द्वारा खरीफ 2025 में सोयाबीन उत्पादक कृषकों के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। भावांतर योजना के संबंध में पिछड़ा वर्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि भावांतर योजना एक किसान हितैषी योजना है, इसका लाभ जिले के हर सोयाबीन

जिले में भावांतर योजना के संचालन के संबंध में कलेक्टर ने दी जानकारी

उत्पादक किसान को मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भावांतर योजना के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलाएं। योजना के सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी सोयाबीन उत्पादक किसानों तक पहुंचाई जाए। जिले के प्रत्येक सोयाबीन उत्पादक किसानों तक योजना के लाभ की जानकारी पहुंचाते हुए, योजना के तहत पंजीयन कराया जाये। विक्रय के दौरान हर मंडी में मॉडल रेट और समर्थन मूल्य का डिसप्ले किया जाए, जिससे किसानों को इनकी जानकारी रहे और व्यापारी व बिचौलिए फायदा न उठा पाएं। जिले के किसानों को भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन फसल के पंजीयन एवं विक्रय में कोई कठिनाई न हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर भी कृषकों और व्यापारियों के साथ बैठकें की जाएं। एसडीएम एवं नोडल अधिकारी विक्रय के दौरान प्रतिदिन मंडियों की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने किसानों की मदद के लिए सभी मंडियों में हेल्प डेस्क बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर ने भावान्तर योजना के बेहतर संचालन के लिये सुझाव भी दिये। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों के पंजीयन और भावांतर योजना के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 03 अक्टूबर से पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो गया है और पंजीयन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक जिले के 5434 सोयाबीन किसानों ने पंजीयन करा लिया है। जिले में आठ कृषि उपज मंडिया हैं। सभी में पंजीयन की कार्यवाही चल रही है। सोयाबीन की बिक्री 07 मंडियों में की जायेगी। कलेक्टर श्री बालागुरू के ने बताया कि सभी मंडियों में किसानों की सुविधा के लिये हेल्प डेस्क बनाये गये हैं। वीसी में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह सहित सभी एसडीएम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुये।

थाने में प्रत्येक फरियादी की शिकायत संवेदनशीलता और गंभीरता से सुनें : एसपी

बैतूल, निप्र। एसपी वीरेंद्र जैन ने भैंसदेही अनुभाग के अंतर्गत आने वाले थानों एवं एसडीओपी कार्यालय भैंसदेही के साथ थाना आठनेर, भैंसदेही और झल्लार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष और अभिलेखों का गहन अवलोकन किया। एसपी ने थाना प्रभारी आठनेर निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार, भैंसदेही निरीक्षक सरविंद धुर्वे और झल्लार उप-निरीक्षक वाहिद खान सहित कर्मचारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत को संवेदनशीलता और गंभीरता से सुना जाए और उसका त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में सौजन्य भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल नागपुर में उपचाररत बच्चों और अभिभावकों से मिले

● परिजनों और अभिभावकों को बंधाया ढांढस ● स्वास्थ्य की सतत निगरानी करने और सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के दिये निर्देश

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल नागपुर में उपचाररत बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। निम्न-स्तरीय कफ सिरप के सेवन से बीमार हुए बच्चे नागपुर में विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स और न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में जाकर उपचार प्राप्त कर रहे पांचों बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि बच्चों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेष टीम लगातार

मॉनिटरिंग करती रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बच्चों के परिजनों और अभिभावकों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। बच्चों के बेहतर से बेहतर उपचार के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। इलाज में आया खर्च सरकार वहन करेगी। बच्चों के पूर्णतः स्वस्थ होने तक सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस पूरे मामले में अत्यंत संवेदनशील है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर डॉ. संजय मिश्रा, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जीएमसी नागपुर, एम्स नागपुर और न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक, शिशु रोग चिकित्सक, विशेषज्ञ और चिकित्सक दल उपस्थित रहे।

ग्रामीण विकास के लिए अधोसंरचना विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं का हो बेहतर क्रियान्वयन : मुख्य सचिव जैन

● स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ायें ● जिला कलेक्टर्स ने दी नवाचारों की जानकारी

भोपाल (नप्र)। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा है कि विकसित प्रदेश का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसरंचना निर्माण और विकास के साथ हितग्राहीमूलक योजनाएँ संचालित हैं। जिला कलेक्टर्स एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी विकास के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी अभियानों में ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सुशासन और अंत्योदय को सफल बनाने के मूल मापदंड के अनुसार कार्य करें।

मुख्य सचिव श्री जैन कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन ग्रामीण विकास विभाग के सत्र को संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में समृद्ध ग्राम एवं विकास खंडों के पुनर्विकास के लिए समावेशी कार्ययोजना पर विशेष ज़ोर दिया गया। साथ ही पंचायतों के राजस्व सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा की गई।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने मुख्यमंत्री वृंदावन

ग्राम योजना की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि जबलपुर, इंदौर, नीमच एवं पन्ना के 14 ग्रामों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री जनधन और धरती आबा कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी। कलेक्टरों से कहा गया कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में समयबद्ध प्रगति के लिए मैदानी अमले का दायित्व निर्धारण करें। ग्रामीण विकास के संदर्भ में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर एक्शन प्वाइंट पर चर्चा की गई। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान की भी समीक्षा की गई लखपति दीदी अभियान को और सशक्त बनाने की अपेक्षा कलक्टरों से की। प्रेजेन्टेशन में बताया गया कि लखपति दीदी योजना में सिंगरौली, टीकमगढ़ और देवास में सबसे बेहतर काम पाया गया।

जिलों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों का किया प्रस्तुतिकरण

कॉन्फ्रेंस में विभिन्न ज़िलों के कलेक्टर ने अपने जिलों में हुए नवाचारों और बेहतर कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया। कलेक्टर खंडवा ने आत्मनिर्भर गौ-शाला और जल संवर्धन अभियान, रायसेन ने जलगंगा संवर्धन अभियान, छिंदवाड़ा ने वाश ऑन व्हील, बड़वानी ने एफआरए पट्टा होल्डर और जिला सीधी ने बेलहा डैम पुनर्जीवन की प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री आज मुंबई में इंटरएक्टिव सेशन में निवेशकों से करेंगे संवाद

रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण सहित विभिन्न सेक्टर्स में निवेश पर होगी चर्चा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सतत् प्रयास अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश शासन ने निवेश-अनुकूल वातावरण को सुदृढ़ करते हुए पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता और उद्योगों के लिए तीव्र गति से अनुमतियाँ प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 अक्टूबर को मुंबई में इंटरएक्टिव सेशन में देश-विदेश के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे।

इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइट गुड्स इन मध्यप्रदेश 9 अक्टूबर को होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र का उद्देश्य निवेशकों को मध्यप्रदेश में उभर रहे औद्योगिक अवसरों से अवगत कराना है, विशेष रूप से मोहासा-बाबई (नर्मदापुरम) में विकसित किए जा रहे पॉवर एवं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (फेस-2) में निवेश को प्रोत्साहन देना है। इस औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

सेशन में देश के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ सिंगापुर, मैक्सिको, कनाडा और इटली सहित विभिन्न देशों के कॉन्सुल जनरल और व्यापारिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हिंदल्को इंडस्ट्रीज़, वेलस्पन ग्रुप, एलएंडटी, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, गॉदरेज इंडस्ट्रीज़, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बजाज ग्रुप, आईपीसीए लैब और रेमंड ग्रुप जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश-संभावनाओं और प्रमुख परियोजनाओं जैसे पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, पीएम मित्र पार्क, फुटवियर पार्क और उद्योग आधारित क्लस्टर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उद्योगपतियों और प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर राज्य में निवेश को लेकर संवाद और डिप्लोमैट राउंडटेबल मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सेशन को श्री वीर एस. अडवाणी, डिप्टी चेयरमैन, सीआईआई वेस्टर्न रीजन एवं प्रबंध निदेशक, ब्लू स्टार लिमिटेड संबोधित करेंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा मध्यप्रदेश की निवेश संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने निवेशकों के प्रति विश्वास और पारदर्शिता का जो वातावरण बनाया है, उसी का परिणाम है कि देश-विदेश की अग्रणी कंपनियाँ अब मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रही हैं। इन सत्रों के माध्यम से प्रदेश में निवेश में वृद्धि होने से औद्योगिक निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे और मध्यप्रदेश उद्योग एवं रोजगार का मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा।

एएसआई समेत तीन को कार से कुचलने की कोशिश

नरसिंहपुर में इनोवा से पीछा किया, टक्कर मारकर गाड़ी भगा ले गया ड्राइवर

नरसिंहपुर (नप्र)। नरसिंहपुर में एएसआई समेत तीन बाइक सवार लोगों को इनोवा कार से कुचलने की कोशिश की गई। घटना 4 अक्टूबर को करेली गुरुद्वारा के पास

की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार को सामने आया है। बाइक पर जबलपुर जिले के चरगवां थाने में पदस्थ एएसआई लालसिंह सेन, अपने साले और बेटे के साथ थे। उन्होंने कार ड्राइवर कुणाल शर्मा उर्फ कान्हा के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है। घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं। इतने में तेज रफ्तार इनोवा बाइक को पीछे से टक्कर मारती है। तीनों लोगों के गिरते ही इनोवा रिवर्स होती है और फिर स्पीड में निकल जाती है। इस दौरान कुछ लोग कार ड्राइवर को रुकने का इशारा करते हैं। जब वो नहीं रुकता तो गाड़ी के पीछे भागते हैं।

एएसआई बोले- गाली देते हुए गाड़ी भगा ले गया ड्राइवर - एएसआई लालसिंह सेन ने मीडिया को बताया- मैं जबलपुर जिले के चरगवां थाने में पदस्थ हूं। 4 तारीख को मेरे घर में एक कार्यक्रम था। मैं छुट्टी लेकर आया, मेरे साथ मेरे साले भी थे। मेरा छोटा बेटा अमित हमें लेने करेली स्टेशन आया था। हम बाइक से घर की तरफ निकले। रात के लगभग साढ़े ग्यारह बज रहे थे। इसी दौरान एक इनोवा कार ने दो-तीन बार हमको क्रॉस किया। जो युवक इनोवा चला रहा था, मैं उसे जानता हूं। उसका नाम कुणाल उर्फ कान्हा है। वो बार-बार गाड़ी की स्पीड कम कर रहा था। इस वजह से हम दो-तीन बार आगे निकल गए। फिर वो स्पीड तेज कर हमसे आगे निकल जाता था। जैसे ही हम करेली गुरुद्वारे के पास पहुंचे, उसने हमारी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मैं वहीं गिर गया लेकिन मेरा साला और बेटा 10 फीट दूर जाकर गिरे। कान्हा गाली देता हुआ चला गया। वहां मौजूद लोगों ने हमें अस्पताल पहुंचाया। कुछ ही देर में करेली पुलिस भी पहुंच गई।

मुख्यमंत्री ने गुरु रामदास के प्रकाश पर्व पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिख पंथ के चतुर्थ गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर उनके पावन चरणों में नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवा, प्रेम और त्याग के प्रतीक गुरु रामदास का सम्पूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। उनकी दिव्य शिक्षाओं के आलोक से मानवता के कल्याण के लिए करुणा, सेवा और समरसता के मार्ग सदैव प्रकाशमान रहेंगे।

इंदौर के डॉक्टर ने छोटे भाई को थार से कुचलवाया

● 10 लाख की सुपारी दी, 6 करोड़ की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था

बड़वाह (खरगोन) (नप्र)। खरगोन जिले में बड़वाह के बलवाड़ा में हत्या की साजिश रचने के केस में फरार डॉ. दीपक शर्मा ने बुधवार को बलवाड़ा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। डॉक्टर पर छोटे भाई की हत्या की साजिश का आरोप है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने अपने छोटे भाई की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपी डॉ. दीपक शर्मा इंदौर के तेजाजी नगर में प्रैक्टिस करता है। उसने पुलिस को बताया है कि वह पेरेंट्स द्वारा पुश्तैनी जमीन छोटे भाई को देने से नाराज था। उसका मकसद 19 बीघा जमीन हड़पना था, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। जमीन के नामांतरण के बाद उसे अपने छोटे भाई संदीप शर्मा पर शक हुआ, जिसके चलते उसने हत्या की साजिश

रची। इसे अंजाम देने की योजना उसने देवास के तनिष रंधावा से बातचीत के बाद बनाई थी, जो उसके पास इलाज के लिए आया था। इसके बाद 29 सितंबर को थार से संदीप को कुचलने की कोशिश की गई।

10 लाख में सौदा, 25 हजार एडवांस दिए थे - डॉ. दीपक शर्मा ने पुलिस को बताया कि सुपारी के तौर पर उसने 25 हजार रुपए एडवांस पेमेंट किया था। 29 सितंबर को उसके साथियों ने एक थार गाड़ी किराए पर ली। संदीप शर्मा का पीछा किया और उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन शुरुआती प्रयासों में सफलता नहीं मिली।

मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन एसपी रविन्द्र वर्मा, एएसपी शकुंतला रुहल, एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत, थाना प्रभारी अनिल कुमार बामनिया, चौकी प्रभारी काटकुट अजय झा और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

थार, तलवार-चाकू और 17000 कैश बरामद - पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल थार गाड़ी, एक तलवार, चाकू और सुपारी का एडवांस पेमेंट 17 हजार कैश बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चेतन पंवार, शुभम आर्य, राहुल वर्मा, आदित्य प्रधान, तनिष रंधावा और राहुल राठौड़ शामिल हैं। पुलिस अभी थार गाड़ी के मालिक विकास सिंह निवासी दतेंरा मुरैना की तलाश कर रही है।

29 सितंबर को थार से जोरदार टक्कर मारी थी - 29 सितंबर की रात जब डॉ. दीपक का भाई संदीप शर्मा काटकूट स्थित अपनी दुकान से बड़ेल गांव अपने घर लौट रहा था, तभी काले रंग की थार गाड़ी में सवार आरोपियों ने पीछा किया और गुजरातीपुरा मोड़ पर पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

भाई जान बचाकर मक्के के खेत में जा छिपा था - टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संदीप सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसके बाद आरोपियों ने हथियार निकालकर उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, संदीप किसी तरह नाले से निकलकर पास के मक्के के खेत में छिपने में सफल रहा। मौके पर अन्य लोगों के पहुंचने पर सभी आरोपी भाग निकले। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को कुंडिया गांव से गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपियों के पास से जब्ती

- सुपारी की राशि में से 17,000 नकद।
- घटना में इस्तेमाल थार गाड़ी (कीमत 15 लाख)।
- हथियार (तलवार-चाकू)।
- गिरफ्तार आरोपियों के नाम चेतन पिता शिवाजीराम पंवार इंदौर, शुभम पिता गबरू आर्य इंदौर, राहुल पिता नरेंद्र वर्मा इंदौर, आदित्य पिता संजय प्रधान इंदौर, तनिष रंधावा देवास, राहुल राठौड़ बलवाड़ा।

आग में झुलसने से दो मासूमों की मौत, मां गंभीर

यूपी के महोबा में तारपीन का तेल गिरने से हादसा, 17 दिन बाद छतरपुर में मौत

छतरपुर (नप्र)। उत्तरप्रदेश के महोबा जिले के डगरिया गांव में आग से झुलसकर दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। हादसा 17 दिन पहले हुआ था। फिलहाल महिला का इलाज छतरपुर जिला अस्पताल में चल रहा है।

खेलते समय हुआ हादसा

यह घटना 17 दिन पहले सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की है। महिला कंचन (23) पति रोहित विश्वकर्मा, उस समय घर में चूल्हे पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान 4 साल की बेटी मुस्कान और डेढ़ साल का बेटा रोशन पास में खेल रहे थे। अचानक बच्चों पर तारपीन का तेल गिर गया, जिससे उनके कपड़े भीग गए। इसके बाद चूल्हे की आग ने तुरंत आग पकड़ ली, जिसमें दोनों बच्चे झुलस गए थे।

मां बचाने में खुद झुलसी

आग लगते ही बच्चों की चीख सुनकर कंचन बच्चों को बचाने दौड़ीं, लेकिन इस

प्रयास में वह भी झुलस गईं। शोर सुनकर पिता रोहित, जो घर के बाहर फर्नीचर का काम कर रहे थे, तुरंत दौड़कर घर पहुंचे और बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाई।

इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत

हादसे के बाद तीनों को महोबा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बेटे रोशन की मौत हो गई। बेटी मुस्कान और मां कंचन को हालत गंभीर होने पर छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां 17 दिनों तक इलाज चलने के बाद मंगलवार-बुधवार की रात मुस्कान की भी मौत हो गई।

महिला का इलाज जारी, बेटी का पोस्टमॉर्टम

मृतक बच्ची मुस्कान का बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम कराया गया। इस बात की पुष्टि अस्पताल चौकी द्वारा बनाए गए पंचनामा में की गई है। वहीं, महिला कंचन की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज छतरपुर जिला अस्पताल में जारी है।

पिता ने बताया घटनाक्रम

पीड़ित पिता रोहित विश्वकर्मा ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं, मुस्कान (4), रोशन (1.5), और कीर्ति (2)। घटना के समय पत्नी खाना बना रही थीं और कीर्ति पास में सो रही थी, जबकि मुस्कान और रोशन खेल रहे थे। तारपीन का तेल गिरते ही आग लगी और यह दर्दनाक हादसा हो गया।

देख रहा है न बिनोद...अब गांव में भी पासपोर्ट बनेगा

वेबसीरीज के डायलॉग के साथ सरकार की पहल 'पंचायत' के फुलेरा गांव पहुंची पासपोर्ट वैन

भोपाल (नप्र)। देशभर में अपनी सादगी और पंचायत के किस्सों के लिए मशहूर फुलेरा गांव, जिसे आप चर्चित वेब सीरीज 'पंचायत' में देखते हैं, असल में मध्यप्रदेश के सीहोर जिले का महोडिया गांव है। अब यही गांव एक नई पहल के लिए चर्चा में है। विदेश मंत्रालय की मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन

महोडिया पहुंच गई है। मंत्रालय ने इस पहल को सोशल मीडिया पर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया। इसमें पासपोर्ट विभाग ने अपने एक्स अकाउंट से सीरीज के लोकप्रिय डायलॉग को नया ट्विस्ट देते हुए साझा किया है।

हां भैया, अब गांव वालों का पासपोर्ट यहीं से बन जाएगा- देख रहा है ना विनोद... पासपोर्ट मोबाइल वैन अब गांव वालों के लिए आ चुकी है। हां भैया, अब गांव वालों का पासपोर्ट यहीं से बन जाएगा। पंचायत सीरीज के इस मशहूर डायलॉग के साथ एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें महोडिया (यानी फुलेरा) गांव की गलियों में यह पासपोर्ट वैन घूमती नजर आ रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल से सोमवार को इस वैन को औपचारिक रूप से रवाना किया गया था। हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरासिया ने फीता काटकर इसे हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने बताया कि इस वैन का मकसद मध्यप्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पासपोर्ट सेवा को पहुंचाना है। जैसे ही यह वैन महोडिया गांव (फुलेरा) पहुंची, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया।

सिरप से मौत- राहुल गांधी 11-12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा आएंगे

परासिया में मृत बच्चों के परिजन से मिलेंगे, एमपी में अब तक 21 बच्चों की मौत

छिंदवाड़ा (नप्र)। मध्यप्रदेश में जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है।इस बीच खबर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 11 या 12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा आएंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, वे परासिया में कफ सिरप पीने से मृत बच्चों के परिजन से मुलाकात करेंगे।

स्मार्ट मीटर के विरोध में भोपाल में कंपनी दफ्तर घेरा

पूर्व मंत्री पीसी बोले-स्मार्ट मीटर का पाकिस्तानी कनेक्शन

भोपाल (नप्र)। भोपाल समेत मध्यप्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को कांग्रेसियों ने बिजली कंपनी का दफ्तर घेर लिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर का पाकिस्तानी कनेक्शन है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ठेका तत्काल रद्द करें। उधर, जबलपुर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर भारत में निर्मित हैं और इन्हें मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनरतले बुधवार दोपहर भोपाल में प्रदर्शन किया गया। सेकंड स्टॉप स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय का घेराव भी किया। पंचशील नगर से रैली के रूप में लोग कंपनी के ऑफिस पहुंचे थे। जहां इंजीनियर को ज्ञापन दिया गया।